देशबन्धु

वर्ष –11 । अंक–203 । सागर, गुरुवार 10 सितम्बर 2026 । पृष्ठ–8 । मूल्य – 2.00 रुपए

बीना-सागर राजमार्ग पर गहरे गड्ढे, पटवारी समेत 4 घायल — पृष्ठ 2

▸ सिमोन द बुवा के देश में नारी उत्पीड़न
▸ असलियत से ज्यादा गणितीय हो सकती है भारत की तेज विकास दर — पृष्ठ 4

▸ खेती को जीविकोपार्जन नहीं, लाभ का व्यवसाय बनाएं — पृष्ठ 6

पीड़ितों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, बंधाया ढांढस — पृष्ठ 8

सार-समाचार

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विवि के नए कुलपति होंगे बिमलेन्द्र कुमार

भोपाल, देशबन्धु। राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष मंगुभाई पटेल ने पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बिमलेन्द्र कुमार को सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्रोफेसर बिमलेन्द्र कुमार को कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए कुलपति नियुक्त किया है।

पुणे में पेपर लीक विवाद के बीच छात्र ने की आत्महत्या

पुणे, एजेंसी। पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पेपर लीक की बार-बार हो रही घटनाओं और आर्थिक तंगी के कारण उसने यह कदम उठाया। मृतक की पहचान प्रथमेश देशमुख के तौर पर हुई है। पुलिस को शक है कि गंभीर आर्थिक परेशानियों, जिसमें 2.5 लाख रुपए का बकाया कर्ज भी शामिल है, के कारण उसने यह कठोर कदम उठाया। इस दुखद घटना ने राज्य में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।

भारत ने नेपाल को भेजी 35 टन राहत और बचाव सामग्री

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय वायुसेना का आठवां विमान बुधवार को 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर नई दिल्ली से काठमांडू भेजा गया। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इसकी जानकारी दी। नेपाल 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से उबरने की कोशिश कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक्स पर कहा, 'भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। एनडीआरएफ के उपकरण, बचाव का सामान, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी चीजों समेत 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर आईएएफ का आठवां विमान काठमांडू के लिए रवाना हो गया।'

मनोज जरांगे बोले- 'सरकार को घुटनों पर लाएंगे'

मुंबई, एजेंसी। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि मराठा समाज मुंबई आने के लिए तैयार है। हम सरकार को घुटनों पर लाएंगे। मराठा समाज पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही, मनोज जरांगे ने मराठा समाज से अपील करते हुए कहा कि हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन कोई भी आत्महत्या न करे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत मनोज जरांगे ने कहा कि अगर मराठा समाज के लोग आत्महत्या करते हैं, तो सरकार को उसका कोई दुख नहीं है। सरकार ने मराठों की जान ली है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा।

हंदवाड़ा में हाइब्रिड पूर्व-आतंकवादी पकड़ा गया

जम्मू, एजेंसी। पुलिस ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में हाइब्रिड मोड में काम कर रहे एक पूर्व-आतंकवादी द्वारा चलाए जा रहे आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एक बयान में पुलिस ने कहा कि हंदवाड़ा पुलिस को एक पूर्व-आतंकवादी की गतिविधियों के बारे में पक्की जानकारी मिली थी। यह व्यक्ति प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल के हिस्से के तौर पर हंदवाड़ा-कुपवाड़ा इलाके में हाइब्रिड आतंकवादी के रूप में काम कर रहा था। तेजी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 21 आरआर और केरिपुब की 22वीं बटालियन के साथ मिलकर हंदवाड़ा शहर में चिन्हित जगह पर एक संयुक्त अभियान चलाया और गहन सुरक्षा जांच के बाद आरोपी को पकड़ लिया।

बंगाल का दौरा करेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन

कोलकाता, एजेंसी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अगले सप्ताह दो दिवसीय दौरे के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं, जहां उनका आयोजन कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। भाजपा की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा कि उनके 15 सितम्बर को राज्य में आने का कार्यक्रम है। वे राज्य पार्टी नेतृत्व के साथ कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। उनके साथ पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष भी होंगे। इन बैठकों में नई राज्य समिति के गठन से लेकर संगठन में जरूरी फेरबदल तक कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

जहरीली शराब से मौतों के मामले में दोषी बचें नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्ती के निर्देश

जिम्मेदारों पर हो कठोर कार्रवाई : मुख्यमंत्री

सागर, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए और नीचे से लेकर ऊपर तक जिम्मेदारी तय कर पूरी गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को बुंदेलखंड मेडिकल महाविद्यालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में जिले की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और असामाजिक गतिविधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है। जिले के साथ आसपास और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गहन जांच अभियान चलाया जाए। जहां भी संदिग्ध गतिविधियों की आशंका हो, तत्काल पड़ताल कर कठोर कार्रवाई की जाए।

डॉ. यादव ने अवैध जहरीली शराब की सामग्री जब्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी सामग्री दोबारा लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई में निष्पक्षता और विवेकशीलता का पूरा ध्यान रखा जाए। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया जाए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और अन्य

माध्यमों से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जाए। नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को साथ लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

कठोर कानून का प्रावधान : मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब के मामलों में कठोर कानून का प्रावधान है। संबंधित धाराओं के तहत हत्या से लेकर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कठोर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध अतिक्रमण अथवा अवैध गतिविधियों के जरिए अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाकर अवैध शराब की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के प्रयास होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने शराब से प्रभावित और बीमार लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने इस घटना में अपने एक से अधिक सदस्यों को खोया है, उनका दुख अत्यंत पीड़ादायक है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शासन के साथ समाज को भी मिलकर प्रयास करना होगा। पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, वीरेंद्र सिंह लोधी, निर्मला सप्रे, ब्रज बिहारी पटेरिया सहित जनप्रतिनिधि, संभागायुक्त दिलीप कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक एसएस चौहान, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया तथा चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।

शराब कांड की होगी न्यायिक जांच

सागर/भोपाल, देशबन्धु। सागर में अवैध शराब मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के साथ तथ्यों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो सके। डॉ. यादव के निर्देश पर दिलीप कुमार ने सागर संभाग के आयुक्त के रूप में कमान संभाल ली है। वहीं, इरशाद वली को सागर संभाग की पुलिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए आईजी बनाया गया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से सरकार की सख्त प्रशासनिक कार्यशैली और जवाबदेही तय करने की नीति स्पष्ट होती है। गौरतलब है कि डॉ. यादव का कहना है कि गंभीर मामलों में लापरवाही अथवा अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

> दिलीप कुमार ने संभागायुक्त की कमान संभाली, इरशाद को आईजी का जिम्मा

छात्र को नोटिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

- सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जारी नोटिस पर सवाल उठाए
- अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगेगे

नई दिल्ली, एजेंसी। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के प्रस्तावित छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कथित तौर पर प्रचार कर रहे एक छात्र को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर पहले ही रद्द की जा चुकी थीं और यह निर्देश दिया गया था कि सीजेपी विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए, तो ऐसा नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत भट्टाचार्य ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने उठाया। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दूसरे वर्ष के एक छात्र को नोटिस जारी कर शांति बनाए रखने के लिए पांच लाख रुपए का निजी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। बताया जाता है कि बाद में यह नोटिस वापस ले लिया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल किया कि विरोध प्रदर्शन से जुड़े छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने के उच्चतम न्यायालय के पहले के निर्देश के बावजूद मजिस्ट्रेट ऐसा नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी उप्र सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। छात्रा व एक्टिविस्ट आकृति चौधरी की एनएसए हिरासत रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत की बेंच को बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जाएगी। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की एनएसए के तहत हिरासत को रद्द कर दिया था और 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह मुआवजा उनकी हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाए। इसमें गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और अन्य अधिकारी शामिल हैं।

राहुल ने सड़कों के गड्ढ़ों पर अफसरों को घेरा

तस्वीरें दिखाकर पूछा, क्यों नहीं हुई कार्रवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिशा समिति की बैठक में रायबरेली की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बैठक के दौरान अधिकारियों को सड़कों के गड्ढों की तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया और सड़क मरम्मत का काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। दिशा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा और सड़कों के रखरखाव को लेकर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा, ताकि सड़कों की स्थिति और मरम्मत कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

जूडा का आंदोलन खत्म, स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत होगी वृद्धि

भोपाल, देशबन्धु। मांगों को लेकर तीन दिन से जारी जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चिकित्सा छात्रों के स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गांधी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी।

उन्होंने मीडिया को बताया कि छात्रों की इस मांग पर पहले से ही चर्चा चल रही थी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस विषय पर सतत संवाद कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त हुए आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और काम पर लौट आए। आंदोलन के चलते बुधवार को भी हमीदिया अस्पताल में बाह्य रोगी सेवाएं प्रभावित रहीं। हालांकि आपात सेवाएं जारी रहीं। उप मुख्यमंत्री ने युवा चिकित्सकों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा भाव और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

महानगरों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्यों को पत्र लिखेगा गृह मंत्रालय

पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायतों के समाधान की कवायद

• **जोगेंद्र सोलंकी**

नई दिल्ली, देशबन्धु। गृह मंत्रालय सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को पत्र लिखने की तैयारी में है, जिसमें उनसे पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए महानगरों में समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया जाएगा। यह फैसला पूर्वोत्तर के लोगों से जुड़े मुद्दों पर मंत्रालय की निगरानी समिति की बैठक में लिया गया। इससे दो दिन पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में मणिपुर के 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह पर क्रूर हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस कदम का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों, जो इस इलाके से बाहर रहते हैं, खासकर बड़े शहरी इलाकों में, उनके साथ होने वाले भेदभाव, परेशानी और दूसरी शिकायतों को दूर करने के मौजूदा सिस्टम को मजबूत करना है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के पूर्वोत्तर डिवीजन के संयुक्त सचिव नीरज कुमार बंसोड़ ने की और इसमें दिल्ली पुलिस, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और गृह मंत्रालय के अधिकारियों समेत अलग-अलग राज्यों और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

> - मणिपुरी संगीतकार की हत्या के बाद जागी सरकार
> - मौजूदा व्यवस्थाओं में बेहतर तालमेल की जरूरत

बैठक में शामिल समिति के दूसरे सदस्यों में डॉ. अलाना गोलमेई, सचिव, पूर्वोत्तर समर्थन केंद्र, नई दिल्ली, डॉ. मिजुम न्योडू, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जोरम मैवियो, मॉनिटरिंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल थे। जोरम मैवियो ने खास बातचीत में बताया कि गृह मंत्रालय शुरू में उन मेट्रो शहरों पर ध्यान देगा जहां पूर्वोत्तर के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। मैवियो ने कहा, 'यह पत्र सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को लिखा जाएगा।' दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, गाजियाबाद और नोएडा समेत कई महानगरीय शहरों में पहले से ही पूर्वोत्तर के लिए नोडल ऑफिसर हैं। हालांकि, मॉनिटरिंग कमिटी के सदस्यों को लगा कि मौजूदा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने और बेहतर तालमेल बिठाने की जरूरत है। समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उसे मजबूत करने की जरूरत पर चर्चा करने के अलावा, प्रस्तावित उत्तर पूर्व सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान की प्रगति की भी समीक्षा की। बता दें कि गृह मंत्रालय की निगरानी समिति का गठन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव से संबंधित मुद्दों और शिकायतों की निगरानी करना और उनका समाधान करना है।

बीज माफियाओं के खिलाफ 'सीड एक्ट' लाने की तैयारी

> देशभर के किसान नेताओं संग संवाद करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के अन्नदाताओं को नकली और घटिया बीजों के नुकसान से हमेशा के लिए सुरक्षित करने की दिशा में मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और आत्मनिर्भर किसान के विजन को अमलीजामा पहनाते हुए केंद्र सरकार एक नया और सख्त 'सीड एक्ट' लाने की तैयारी में है। इस कानून को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को देशभर के प्रमुख किसान संगठनों के शीर्ष नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीड कानून के मसौदे पर सीधे किसानों के जमीनी अनुभव, सुझाव और पक्ष को शामिल करना है ताकि बीज माफियाओं के खिलाफ एक अचूक और प्रभावी व्यवस्था खड़ी की जा सके। प्रस्तावित नए 'सीड एक्ट' के तहत नकली, मिलावटी या घटिया बीज बेचने वाली कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ भारी जुर्माने और जेल की सजा जैसे बेहद सख्त कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं। कई बार खराब बीज के कारण किसान की महीनों की गाढ़ी कमाई और खून-पसीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख है कि कानून ऐसा बने जो बीज की गुणवत्ता और पारदर्शी ट्रेसिंग सिस्टम की शत-प्रतिशत गारंटी दे, साथ ही किसानों के पारंपरिक बीजों के अधिकारों की भी रक्षा करे।

भाजपा को कांग्रेस से 7 गुना ज्यादा चंदा मिला

नई दिल्ली, एजेंसी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस की चुनावी कमाई में बड़ा अंतर सामने आया है। चुनाव आयोग के सामने दाखिल खर्च और आय से जुड़े ब्योरे के मुताबिक, भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय को इस अवधि में करीब 1,472.8 करोड़ रुपए मिले। यह कांग्रेस की पांचों राज्यों और केंद्रीय इकाइयों की कुल शुद्ध प्राप्तियों 207.17 करोड़ रुपए से सात गुना से भी ज्यादा है। भाजपा का उपलब्ध आंकड़ा केवल केंद्रीय मुख्यालय का है।

> - 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को मिला 1,473 करोड़ चंदा
> - भाजपा के पास 7,627.2 करोड़ रुपए

15 मार्च से 6 मई तक असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्रीय मुख्यालय और पांचों राज्यों की इकाइयों को मिलाकर 207.17 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां बताईं। उसका कुल चुनावी खर्च 248.55 करोड़ रुपये रहा। दूसरी ओर, भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय को इसी अवधि में 1,472.8 करोड़ रुपए मिले। भाजपा के केरल और पश्चिम बंगाल चुनावों के खर्च से जुड़े ब्योरे अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इसलिए भाजपा की कुल प्राप्तियां उपलब्ध आंकड़े से भी अधिक हो सकती हैं। भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय की वित्तीय स्थिति में चुनाव अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई। 15 मार्च को उसके पास करीब 6,722.6 करोड़ रुपए का समापन शेष था। 6 मई तक यह बढ़कर 7,627.2 करोड़ रुपए हो गया। यानी चुनाव अवधि में केंद्रीय मुख्यालय के पास मौजूद रकम में करीब 904.6 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई।

कांग्रेस ने कागजी पार्टियों के चंदा मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की

चंदे के नाम पर 10 हजार करोड़ की हेराफेरी

- भाजपा ने कई को अपनी सी टीम के रूप में खड़ा किया
- देशभर में ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या करीब 3260

नई दिल्ली, देशबन्धु। कागजी पार्टियों के जरिए 10 हजार करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसकी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने देशभर में बहुत सारे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सी टीम के रूप में खड़ा किया है।

बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कुछ दिनों पहले एक मीडिया संस्थान द्वारा प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए कहा कि यह देश का सबसे बड़ा टैक्स घोटाला है। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें गंभीर अनियमितता नजर आ रही है, लेकिन सरकार अपने चहेतों को बचाने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में एडीआर की रिपोर्ट आई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। झारखंड के कुछ आयकर अधिकारियों ने इस फर्जीवाड़े को आपराधिक मामला बताते हुए मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोहिल आरोप लगाया कि भाजपा ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त कई दलों को अपनी सी टीम के रूप में खड़ा किया है, जिनके जरिए टैक्स की चोरी और काले धन को सफेद बनाने का काम किया जा रहा है। देशभर में ऐसे दलों की संख्या करीब 3260 है। इन फर्जी दलों को चंदा देकर टैक्स चोरी करने वाले बोगस डोनर्स पर आयकर कानून के तहत 200 फीसदी जुर्माना और आपराधिक मामले दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इस फर्जीवाड़े में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स व फर्जी दलों के कर्ता धर्ताओं और चंदा देने वाली कंपनियों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही यह भी बताया जाए कि इन फर्जी दलों के चलाने वाले कितने लोग अब भाजपा में हैं? गोहिल का कहना था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे पर टैक्स की छूट का प्रावधान है। इसी का दुरुपयोग कर इन फर्जी दलों को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया गया। इसके बदले इन फर्जी दलों के लोगों ने दो से 15 फीसदी कमीशन काटकर शेष राशि चंदा देने वालों को लौटा दी। आयकर विभाग और ट्रिब्यूनल ने भी इस फर्जीवाड़े को स्वीकार किया है।

काले धन को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे राजनीतिक दलों को मिले चंदे और उनके खर्च का पूरा ब्योरा अपनी वेबसाइट पर जारी करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। काले धन को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन इस मामले पर अभी तक खामोशी क्यों है? इस मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाए ताकि पूरा सच सामने आ सके।

बीना-सागर राजमार्ग पर गहरे गड्ढे, पटवारी समेत 4 घायल

सागर से आ रहे थे वापस, टोल वसूली के बावजूद सड़क खराब

बीना, देशबन्धु। बीना-सागर नेशनल हाईवे 934 पर बने गहरे गड्ढे राहगीरों के लिये खतरनाक बने हुये हैं। सड़क की खराब हालत के कारण आये दिन वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। मंगलवार रात सागर से लौट रहे पटवारी हल्का नंबर.1 शुभम शुक्ला की बाइक सड़क के गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी दिन जरुआखेड़ा निवासी अरविंद विश्वकर्मा, निक्की चौबे और गौरव प्रजापति भी अपनी बाइक के साथ सड़क के गड्ढे में गिरकर घायल हो गये। तीनों को भी अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर गड्ढे इतने गहरे हो गये हैं कि रात के समय वाहन चालकों को इनका अंदाजा नहीं लग पाता। अचानक बाइक या दूसरे वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। सड़क की खराब हालत को लेकर जरुआखेड़ा निवासी अमित कटारे ने 12 अगस्त को मप्र शासन के लोकपथ ऐप पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत का नंबर 16249 है। अमित का आरोप है कि शिकायत के बाद भी मौके पर सड़क की असली मरम्मत नही की गई। अमित कटारे ने बताया कि शिकायत करने के बाद उन्हें ठेकेदार की तरफ से धमकाया भी गया। उनका आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने लोकपथ ऐप पर सड़क की मरम्मत का फोटो अपलोड कर शिकायत का समाधान दिखा दिया। जबकि मौके पर आज तक उन गड्ढों की मरम्मत नहीं हुई है। पहली शिकायत के बाद भी सड़क की स्थिति नहीं सुधरने पर अमित कटारे ने बुधवार को इसी स्थान सहित दो अन्य जगहों पर सड़क के गड्ढों को लेकर लोकपथ ऐप पर दोबारा शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायतों के क्र. 18607 और 18608 हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत कर दी जाती तो लगातार हो रहे हादसों को रोका जा सकता था। सागर-बीना मार्ग पर वाहन चालकों से टोल टैक्स की वसूली भी की जा रही है। इसके बावजूद सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुये हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब वाहन चालकों से सड़क के उपयोग के लिये टोल वसूला जा रहा है तो सड़क की नियमित मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग और ठेकेदार की है। लोगों ने मांग की है कि हादसों को रोकने के लिये गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराई जाये। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग के संभागीय ईई अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बारिश शुरू होने से पहले संबंधित सड़क के गड्ढों को भरवाया गया था। लगातार बारिश होने के कारण सड़क पर दोबारा गड्ढे हो गये हैं। एक-दो दिन में गड्ढों की मरम्मत का कार्य पूरा करा दिया जायेगा।

सेवा संकल्प अभियान को लेकर सागर विधानसभा के चारों मंडलों की बैठक संपन्न

सागर, देशबन्धु। जिला भाजपा कार्यालय में सागर विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि विधायक शैलेंद्र जैन एवं अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने की। बैठक में प्रधानमंत्री के लोकसेवक के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत होने वाले सेवा एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की यात्रा देश के लिये प्रेरणादायी है। सेवा संकल्प अभियान सेवा, समर्पण और जनकल्याण की भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर तक प्रभावी बनाते हुये अधिक से अधिक लोगों को सेवा गतिविधियों से जोड़ने का आह्वान किया। श्याम तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की लोकसेवा यात्रा त्याग, तपस्या और राष्ट्र समर्पण की मिसाल है। अभियान की सफलता के लिये प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभाते हुये सेवा कार्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। बैठक में आगामी कार्यक्रमों के लिये दायित्व निर्धारण, मंडल एवं बूथ स्तर पर समन्वय तथा विभिन्न सेवा गतिविधियों के सफल आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मेघा दुबे सहित भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी, मंडल कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

स्व सहायता समूह की महिलाओं ने निकाली नशा मुक्ति रैली

सागर, देशबन्धु। स्व.सहायता समूहों की महिलाओं ने बंडा एवं शाहगढ़ विकासखंड के विभिन्न गांवों में जन जागरूकता रैली निकाली। बंडा के पाटन, बम्होरी भेड़ा, साजी तथा शाहगढ़ के पापेट, गूगरा, दलपतपुर एवं नोराज में निकाली गई रैली के दौरान महिलाओं ने नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो नशा मुक्त हो अपना गांव और नशे से दूरी है जरूरी जैसे नारों के माध्यम से ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। रैली के समापन पर ग्रामीणों को नशे से दूर रहने और परिवार एवं समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ दिलाई। समूह की सदस्यों ने कहा कि नशे के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के साथ युवा पीढ़ी भी भटकती है। उन्होंने गांव-गांव महिलाओं एवं युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में आजीविका मिशन के अधिकारी, सामुदायिक रिसोर्स पर्सन, स्व.सहायता समूहों की सदस्यायें एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जहरीली शराब कांड : पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे सांसद-विधायक

बंडा, देशबन्धु। संदिग्ध जहरीली अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद बंडा विधानसभा क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की गंभीरता के बीच सोमवार को दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लोधी और बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह ने प्रभावित गांवों का दौरा कर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने छापरी, बमूरा, पाटन, बुढना, रवारा, धुरमार और पापेट पहुंचकर पीड़ित परिवारों का दुख साझा किया और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। मृतकों के परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुये सांसद और विधायक ने संवेदना व्यक्त की तथा इस मुश्किल घड़ी में परिवारों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि पीड़ित परिवारों की पीड़ा को गंभीरता से लिया जा रहा है। शासन की ओर से मिलने वाली हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि परिवारों की जरूरतों और मांगों को शासन के समक्ष रखा जायेगा, ताकि उन्हें उचित राहत और सहयोग मिल सके। वहीं विधायक वीरेंद्र सिंह ने दो टूक कहा कि घटना के जिम्मेदार लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग शासन प्रशासन के समक्ष रखने की बात कही। सांसद और विधायक ने प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों से भी चर्चा की और घटना से जुड़े हालात की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से अवैध शराब और नशे के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अवैध शराब के नेटवर्क को खत्म करने के लिये प्रशासनिक कार्यवाही के साथ सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। राहुल सिंह लोधी और वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने तथा क्षेत्र में अवैध शराब के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर की जा रही कार्यवाही पर भी नजर रखी जा रही है। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता जाहरसिंह बमूरा, जिला उपाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह महूंना, छापरी मंडल अध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह, सूरज सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

संत रविदास के विचार मजबूत राष्ट्र निर्माण की आधारशिला: आकाश सिंह

सागर, देशबन्धु। सुरखी विधानसभा में संत रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता का संदेश लेकर निकाली जा रही समरसता यात्रा तीसरे दिन बुधवार को रिछई, करहद, सेवन, मसुरहाई एवं सीहोरा में रही। यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। सीहोरा में यात्रा का समापन हुआ। युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुये कहा कि संत रविदास का जीवन केवल भक्ति का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि समतामूलक समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है। व्यक्ति की पहचान जाति, ऊंच-नीच या आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके कर्म, चरित्र और मानवता से होनी चाहिये। संत रविदास ने सामाजिक भेदभाव के दौर में समाज को समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भारत विविधताओं वाला देश है, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद हमारी पहचान भारतीय के रूप में एक है। उन्होंने युवाओं से समाज को जोड़ने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। कहा कि युवा मतभेदों को संवाद के माध्यम से दूर करें, हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़े और संत रविदास जैसे महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। देश की प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि समाज का अंतिम व्यक्ति कितना सम्मानित, सुरक्षित और सशक्त महसूस करता है। प्रदेश अनु. जाति के उपाध्यक्ष अमित कछवाह ने यात्रा की सराहना करते हुये कहा कि यह प्रदेश की प्रभावी यात्राओं में से एक है। आकाश सिंह द्वारा यात्रा को सामाजिक समरसता से जोड़ने के प्रयास से विभिन्न समाजों के बीच अपनत्व और भाईचारे की भावना मजबूत हो रही है।

जिला महामंत्री चेतराम ने यात्रा की प्रशंसा करते हुये कहा कि सुरखी विधानसभा की यात्रा में लोगों का प्रेम, सद्भाव और आपसी भाईचारा विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर आकाश सिंह ने रविदास मंदिरों से जुड़े प्रमुख संतों एवं गुरुओं का सम्मान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, संत समाज एवं विभिन्न समाजों के नागरिक मौजूद रहे।

पुलिस हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों पर कार्रवाई, 4 स्थानों से अवैध शराब बरामद

सागर, देशबन्धु। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ पुलिस के अभियान को आमजन का व्यापक सहयोग मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 7701055235 पर एक दिन में ही 69 सूचनायें प्राप्त हुई। पुलिस ने प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर तत्काल तस्दीक एवं कार्यवाही कराई। अब तक चार स्थानों पर अवैध शराब पकड़ी गई, जबकि एक सूचना पर सट्टे का प्रकरण दर्ज किया है। शेष सूचनाओं पर भी जांच एवं वैधानिक कार्यवाही जारी है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने सूचना देने वाले नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि अवैध शराब एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित प्रत्येक सूचना पुलिस के लिये महत्वपूर्ण है। नागरिक बिना भय या संकोच के अपने आसपास होने वाली अवैध गतिविधियों की जानकारी दें, जिस पर सत्यापन के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि हेल्पलाइन पर सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जायेगी। नागरिक अवैध शराब के साथ जुआ, सट्टा एवं अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी भी हेल्पलाइन पर दे सकते हैं।

विहिप-बजरंग दल देवरी प्रखंड की बैठक संपन्न, नवीन दायित्वों की घोषणा

देवरी, देशबन्धु। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल देवरी प्रखंड की बैठक जवाहर वार्ड स्थित विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष मिथिलेश ब्रह्मपुरिया के निवास पर आयोजित की गई। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री जितेंद्र एवं प्रांत बलोपासना प्रमुख अनुज सिंह परिहार उपस्थित रहे। प्रांत संगठन मंत्री जितेंद्र ने कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद की कार्यप्रणाली एवं संगठन की परंपरा से अवगत कराते हुये संगठन को मजबूत बनाने और समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज को एकजुट कर राष्ट्र एवं समाज की सेवा के लिये कार्य करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन के उद्देश्यों एवं दायित्वों के संबंध में मार्गदर्शन दिया। अनुज सिंह परिहार ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुये कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री संजीव सोनी द्वारा बजरंग दल के नवीन दायित्वों की घोषणा की गई। आजाद कुशवाहा को बजरंग दल देवरी प्रखंड संयोजक तथा शिवा नामदेव को नगर संयोजक, रविंद्र सेन को प्रखंड सहसंयोजक और गौरव पटेल को नगर सहसंयोजक का दायित्व सौंपा। बैठक में विश्व हिंदू परिषद जिला कोषाध्यक्ष मिथिलेश ब्रह्मपुरिया, बजरंग दल के पूर्व संयोजक नारायण पटेल, विहिप देवरी अध्यक्ष लीलाधर यादव, प्रखंड मंत्री नीरज नामदेव, उपाध्यक्ष बाबूराम सेन, धर्मेंद्र कोष्टी, सहसंयोजक राजेंद्र पटेल, नगर अध्यक्ष अभिषेक बड़कुल, नगर उपाध्यक्ष केसु लखेरा, सुरक्षा प्रमुख दीपक विश्वकर्मा, सहमंत्री अनूप विश्वकर्मा, विद्यार्थी प्रमुख सजल, सह.विद्यार्थी प्रमुख राज नामदेव आदि उपस्थित रहे। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नवीन दायित्व प्राप्त पदाधिकारियों को शुभकामनायें देते हुये संगठन के कार्यों को निष्ठा एवं सक्रियता के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रंजना वर्मा सम्मानित

सागर, देशबन्धु। केंद्रीय विद्यालय क्र.4 डीएचएसजी विवि सागर की रंजना वर्मा को शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक दक्षता एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिये उनके निरंतर समर्पित प्रयासों की महत्वपूर्ण पहचान है। रंजना वर्मा ने शारीरिक शिक्षा को केवल पारंपरिक खेल अभ्यास तक सीमित न रखते हुये अभिनव तरीकों को अपनाकर विद्यार्थियों के लिये खेलों को अधिक रोचक, चुनौतीपूर्ण और लक्ष्य आधारित बनाने का प्रयास किया है। उनके इन नवाचारों से विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक भावना, टीमवर्क, नेतृत्व और अनुशासन जैसे गुणों को विकसित करने में भी मदद मिली है। विद्यालय में उपलब्ध सीमित स्थान एवं संसाधनों को बाधा न मानते हुये श्रीमती वर्मा ने बेहतर योजना एवं नवाचार के माध्यम से उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया। उनकी कार्यशैली में खेल शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को भी विशेष महत्व दिया जाता है। उनके प्रयासों में विद्यालय प्रबंधन का सहयोग भी उल्लेखनीय रहा है।

प्राचार्य राजेन्द्र सिंह वर्मा ने खेल एवं शारीरिक शिक्षा को विद्यालय की समग्र शैक्षिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग मानते हुये आवश्यक दिशा निर्देश, प्रोत्साहन एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया। विद्यालय परिवार का मानना है कि राष्ट्रीय गौरव सम्मान.2026 केवल रंजना वर्मा का व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि यह प्राचार्य के कुशल नेतृत्व, खेल शिक्षिका की कर्मठता, विद्यार्थियों की मेहनत और केंद्रीय विद्यालय क्र.4 की सकारात्मक खेल संस्कृति का सामूहिक सम्मान है। यह उपलब्धि विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिये प्रेरणादायी है।

आज से 17 तक छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर होंगे छात्र संवाद

सागर, देशबन्धु। इंदौर में आयोजित होने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर शहर में छात्र संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जायेगी। कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवा कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, ब्लॉक अध्यक्षों सहित विभिन्न मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में महेश जाटव ने कहा कि इंदौर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम के संदर्भ में सागर में छात्र संवाद आयोजित किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रहित से जुड़े विषयों पर संवाद किया जायेगा। उन्होंने पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुये आयोजन को व्यवस्थित एवं सफल बनाने का आह्वान किया। साथ ही इंदौर में आयोजित होने वाले मुख्य छात्रों की गूंज कार्यक्रम का सागर में लाइव प्रसारण किया जायेगा। इसके लिये स्थान का चयन किया जा रहा है। संगठन मंत्री रामकुमार पचौरी ने कहा कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित वे स्वयं भी छात्र संवाद कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वरिष्ठ कांग्रेसजनों के सहयोग से सभी कार्यक्रमों को सफल बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों से सीधे संवाद की यह पहल उनके मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगी। बैठक में सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे, सागर साहू, अक्षत कोठारी, डॉ. किरण लता सोनी, प्रवक्ता कमलेश तिवारी, ऋचा सिंह, दीनदयाल तिवारी सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बारिश से श्रीराम कॉलोनी में जलभराव, कीचड़ से दलदल बनी गलियां

सड़क-नाली नहीं होने से रहवासी परेशान, स्थायी समाधान की मांग

बीना, देशबन्धु। शहर से लगी बरदौरा ग्राम पंचायत की श्रीराम कॉलोनी में बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कॉलोनी में पक्की सड़क और नालियों की व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी गलियों में जमा हो रहा है। कई जगह कीचड़ और गंदगी के कारण दलदल जैसी स्थिति बन गई है। पानी की निकासी नहीं होने से गंदा पानी लंबे समय तक जमा रहता है। इससे बदबू के साथ मच्छरों की संख्या भी बढ़ गई है। रहवासियों के मुताबिक बच्चों को स्कूल भेजने और बुजुर्गों को गलियों से निकलने में परेशानी होती है। महिलाओं को भी रोजमर्रा के कामों के लिये कीचड़ भरी गलियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। कॉलोनीवासियों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। हर साल बारिश के दौरान कच्ची गलियां कीचड़ से भर जाती हैं और घरों के आसपास पानी जमा हो जाता है। लोगों ने कॉलोनाइजर के अलावा बरदौरा पंचायत और एसडीएम कार्यालय में कई बार शिकायत की, लेकिन सड़क और नाली निर्माण का स्थायी समाधान नहीं हुआ। रहवासियों का कहना है कि लंबे समय तक जलभराव रहने से मच्छर पनपने और संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल पानी निकासी की व्यवस्था कराने के साथ सड़क और नालियों का स्थायी निर्माण कराने की मांग की है। शहर से लगी ग्राम पंचायतों में खेतों को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर कॉलोनियां विकसित किये जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई कॉलोनियों में सड़क, नाली, बिजली और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधायें नही हैं। बारिश के दौरान इन इलाकों की स्थिति और खराब हो जाती है। श्रीराम कॉलोनी की समस्या ने शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हो रही कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किये हैं। रहवासियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान प्रक्रिया और जिम्मेदारी के फेर में अटका हुआ है। कॉलोनीवासियों ने जल्द सड़क और नाली निर्माण शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने के लिये मजबूर होंगे। बरदौरा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कुशवाहा ने बताया कि कॉलोनी की जमीन और सड़क को लेकर दानपत्र की स्थिति स्पष्ट नही है। इसी वजह से पंचायत की राशि से निर्माण कार्य नही कराया जा सकता। कुछ दिन पहले इस संबंध में अधिकारियों को लिखित जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है।

कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सौंपा 8 सूत्रीय ज्ञापन

अवैध शराब, नशा, जुआ-सट्टा और महिला अपराधों पर कार्रवाई की मांग

देवरीकलां, देशबन्धु। देवरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी ने पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक के नाम 8 सूत्रीय ज्ञापन देवरी थाना प्रभारी को सौंपकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन सौंपने से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गैस एजेंसी के पास एकत्रित हुये। यहां से रैली के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुये एसडीओपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुये पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। एसडीओपी कार्यालय में पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हर्ष यादव ने पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुये आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था और आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा को छोड़कर राजनीतिक जी.हुजूरी में व्यस्त है। देवरी विधानसभा के देवरी, केसली, गौरझामर और महाराजपुर थाना क्षेत्रों में अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, जिससे आम नागरिकों में सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। उन्होंने क्षेत्र में अवैध शराब, गांजा, स्मैक एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, जुआ-सट्टा, चोरी, लूट, मारपीट, गोलीकांड, महिला अपराध तथा नाबालिग बालिकाओं के गुमशुदगी और अपहरण जैसी घटनाओं पर चिंता जताई। ज्ञापन में बंडा विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस ने घटना में मृतकों की संख्या और उससे जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की, साथ ही पुलिस अथवा आबकारी विभाग के

अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही की मांग की। मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने, मामले की सीबीआई जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग भी रखी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देवरी विधानसभा के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। क्षेत्र में स्मैक पाउडर और अन्य मादक पदार्थों के कारोबार को लेकर कांग्रेस ने चिंता जताई। नेताओं ने प्रमुख सप्लायरों, स्थानीय पेडलरों और बड़े तस्करों की पहचान कर पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच करने, साथ ही सागर, दमोह, नरसिंहपुर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े कथित नेटवर्क की संयुक्त जांच करने, देवरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों में हुई चोरी की घटनाओं पर भी चिंता जताई, कांग्रेस ने सभी मामलों की गंभीरता से जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गई सामग्री की बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग की। देवरी एवं केसली विकासखंड मुख्यालय के साथ गौरझामर और महाराजपुर क्षेत्रों में जुआ सट्टा और रिस्क के संचालन का मुद्दा भी उठाया। आरोप लगाया कि इन गतिविधियों को राजनीतिक संरक्षण और पुलिस की मिलीभगत मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। चारों थाना क्षेत्रों में महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ सहित अन्य महिला अपराधों की थाना वार समीक्षा करने, लंबित मामलों का समय सीमा में निराकरण, महिला पुलिसकर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने, स्कूल.कॉलेजों के आसपास छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई, स्कूल-कॉलेज खुलने और छुट्टी के समय विशेष पुलिस व्यवस्था करने तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त बढ़ाने, इसके अलावा रात के समय धार्मिक स्थलों, बाजार क्षेत्रों, सुनसान मार्गों, संवेदनशील गांवों और अपराध प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस गश्त प्रभावी बनाने की मांग की। पूर्व मंत्री यादव ने कहा कि देवरी विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां आम नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण परिवारों के लिये गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अवैध शराब, मादक पदार्थों, जुआ सट्टा और संगठित अपराधों पर समय रहते कठोर कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। इस अवसर पर आशीष वावा राजौरिया, गौरव पाण्डेय, अनंतराम रजक, आंचल आठया, विजय गुरु, शरद सोनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

नल जल योजना की खुदाई बनी हादसे का कारण

दो दिन में एक दर्जन से अधिक बाइक सवार गिरे, कई घायल

मालथौन, देशबन्धु। नलजल योजना के तहत पाइप लाइन डालने के लिये स्टेट हाईवे की सड़क की गई खुदाई वाहन चालकों के लिये परेशानी का सबब बन गई। मालथौन-खिमलासा रोड पर अण्डेला के पास गौधाम मार्ग के सामने खुदाई वाली जगह पर सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से दो दिन में एक दर्जन से अधिक बाइक सवार गिरकर घायल हो गये। रामाधार और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नलजल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के लिये स्टेट हाईवे की सड़क खोदी गई थी। काम पूरा होने के बाद खुदाई वाली जगह को पर्याप्त रूप से समतल नहीं किया गया। वही वाहन चालकों को सावधान करने के लिये न तो पर्याप्त चेतावनी संकेत लगाये गये और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये। अचानक सामने आने वाली नाली और सड़क की खुदाई के कारण बाइक सवारों का संतुलन बिगड़ता रहा। देखते ही देखते दो दिनों में कई लोग हादसे का शिकार हो गये। इनमें कई वाहन चालकों के घायल होने की बात सामने आई है। लगातार हो रहे हादसों और लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित ठेकेदार ने आनन-फानन में खुदाई वाली जगह पर सीसी डालकर नाली को भरने का काम शुरू कर दिया। हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि सड़क की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। हादसों के बाद सड़क को भरने की कार्यवाही शुरू होने से जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते चेतावनी संकेत और सुरक्षा के इंतजाम किये गये होते तो कई हादसों को टाला जा सकता था। अब सवाल है कि लापरवाही के लिये जिम्मेदार कौन है और हादसों में घायल हुये लोगों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा।

खुरई की भीतरी सड़कों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक की मांग

खुरई, देशबन्धु। नगर की सड़कों पर बढ़ते भारी वाहनों के दबाव और सड़क क्षतिग्रस्त होने की समस्या को देखते हुये नगर पालिका ने अहम पहल की है। सीएमओ राजेश मेहतेले ने थाना प्रभारी खुरई को पत्र भेजकर नगर की भीतरी सीमा में 6 टन से अधिक भार वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। नपा के अनुसार आमजन की सुविधा के लिये निकाय द्वारा निर्मित एवं संधारित सड़कों की भार क्षमता लगभग 6 से 8 टन तक है। इसके बावजूद नगर के मुख्य मार्गों से वर्तमान में 12 से 30 टन तक भार वाले भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के लगातार गुजरने से सड़कों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और उनके क्षतिग्रस्त होने की स्थिति बन रही है। पत्र में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुये कहा है कि इससे न केवल सड़कों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी सुचारु होगी। भारी वाहनों की आवाजाही कम होने से दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी आने और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन मिलने की उम्मीद है। नपा की इस पहल के बाद अब पुलिस प्रशासन द्वारा भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने को लेकर कार्यवाही किये जाने की उम्मीद है।

31 दिसंबर से पहले होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा

सागर, देशबन्धु। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मप्र एवं आयुक्त लोक शिक्षण की मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑफलाइन कराने की तैयारी है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ऑफलाइन परीक्षा कराने में असमर्थता जताये जाने के बाद विभाग अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। संभावना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से परीक्षा कराई जाये, हालांकि अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा एक ही बार आयोजित की जायेगी और इसे 31 दिसंबर से पहले कराने का प्रयास है। परीक्षा से शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी तथा यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कराई जा रही है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने परीक्षा का विरोध करते हुये कहा कि मप्र में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अन्य राज्यों से अलग रही है, इसलिये पुनः टीईटी कराना उचित नहीं है। मोर्चा के प्रांतीय संयोजक राकेश दुबे ने कहा कि वर्ष 2010 में आरटीई अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा से मुक्त रखा जाना चाहिये। मोर्चा ने सरकार से तमिलनाडु की तर्ज पर विधानसभा में टीईटी के विरोध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की मांग की है। साथ ही शिक्षकों से टीईटी का फॉर्म नहीं भरने की अपील की है। बैठक में राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह, अध्यापक संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक मंडल के जगदीश यादव, राकेश दुबे, राकेश नायक, डी के सिंगोर, राकेश पटेल, जितेंद्र शाक्य, उपेंद्र कौशल, दिनेश शुक्ला, दर्शन ओढ़, हीरानंद नरवरिया, नीलेश आर्य उपस्थित रहे।

3-4 दिन में फिर दौड़ेंगी खुरई की निःशुल्क छात्र बसें

खुरई, देशबन्धु। नगरीय क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिये पूर्व मंत्री एवं विधायक भूपेंद्र सिंह द्वारा संचालित निःशुल्क छात्र बस सेवा जल्द ही पुनः शुरू होने की संभावना है। तीनों बसों की फिटनेस एवं बीमा अवधि समाप्त होने के कारण फिलहाल बसों का संचालन रोक दिया गया है। आरटीओ कार्यालय सागर में इनके नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है। जानकारी के अनुसार बसों के फिटनेस एवं बीमा नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। आधार अपडेशन सहित आवश्यक औपचारिकतायें पूरी होने के बाद निर्धारित शुल्क जमा कर फिटनेस की प्रक्रिया पूर्ण कराई जायेगी। इसके बाद बसों का विधिवत संचालन शुरू किया जायेगा। आगामी 3 से 4 दिनों में आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों निःशुल्क छात्र बसों का संचालन पुनः शुरू होने की उम्मीद है। बस सेवा बहाल होने से खुरई क्षेत्र के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

एक यात्री बस का फिटनेस निरस्त, स्कूल बस सहित चार वाहन जब्त

स्कूल एवं यात्री बसों की सघन चेकिंग, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई

सागर, देशबन्धु। यात्री एवं स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिये क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा 9 सितंबर को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के निर्देशन में गठित दो दलों ने मालथौन, देवरी, शहरी क्षेत्र एवं कर्रापुर मार्ग पर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान एक यात्री बस का फिटनेस प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त किया गया। बस क्र. यूपी 93 सीटी 0789 में निर्धारित अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स नही पाये गये, जबकि पीछे के कांच पर लोहे की जाली लगी मिली। कार्यवाही मोटरयान अधिनियम की धारा 56(4) के तहत की गई। फिटनेस निरस्ती की अवधि में वाहन का पंजीयन एवं परमिट भी निलंबित रहेगा। वही शहरी क्षेत्र एवं कर्रापुर में जांच के दौरान बिना फिटनेस बच्चों का परिवहन कर रही एक स्कूल बस एमपी 15 जेडडी 6985 तथा तीन यात्री बसों में सुरक्षा मानकों की कमी पाए जाने पर उन्हें जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया। चेकिंग के दौरान छह यात्री वाहनों में चालक लाइसेंस, आवश्यक दस्तावेज, निर्धारित अग्निशमन यंत्र, एचएसआरपी नंबर प्लेट एवं रेडियम रिफ्लेक्टर जैसी कमियां पाई गई। कुछ वाहनों में चालक निर्धारित गणवेश में नहीं पाये गये। इसके अलावा 10 अन्य वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुये कुल 63 हजार रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया। परिवहन विभाग द्वारा स्लीपर कोच बसों में एआईएस 119 के सुरक्षा प्रावधानों की भी जांच की जा रही है। इनमें फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन सिस्टम, निर्धारित संख्या में आपातकालीन निकास द्वार तथा अग्निशमन यंत्र सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें प्रमुख हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि संचालन के दौरान वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ रखे।

जहरीली शराब के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

गौरझामर, देशबन्धु। जिले के बंडा क्षेत्र में अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद गौरझामर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोलते हुये 9 सितंबर को थाना प्रभारी गौरझामर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने बंडा क्षेत्र में अवैध जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने का दावा करते हुये मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अवैध शराब के कारण कई परिवार प्रभावित हुये हैं और छोटे बच्चों एवं महिलाओं के सामने भी संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। कांग्रेस ने गौरझामर एवं देवरी विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक, अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही तथा शराब कारोबार को संरक्षण देने वाले अधिकारियो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। साथ ही अवैध शराब के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग और थानों में प्रतिमाह रक्षा समिति की बैठक आयोजित करने की मांग भी की गई। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अवैध शराब के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्रवाई से पहले सूचना लीक होने का आरोप, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

बीना, देशबन्धु। बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब बिक्री के विरोध में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। इसके बाद तहसीलदार अंबर पंथी को राज्यपाल के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदर यादव ने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब बिक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं। इंदर यादव ने एक दिन पहले मंजूर किये गये शराब के एक ब्रांड पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि इसी ब्रांड की शराब से मौतें हुई थी। कांग्रेस ने मामले की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीना क्षेत्र के गांवों में खुलेआम शराब बेची जा रही है। उन्होंने कार्यवाही से पहले संबंधित लोगों तक सूचना पहुंचने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से मुलाकात कर सेमरखेड़ी क्षेत्र का मामला उठाया। नेताओं ने बताया कि एक व्यक्ति ने पुलिस को अवैध शराब बिक्री की सूचना दी थी। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यवाही से पहले ही शराब बेचने वालों को इसकी जानकारी मिल गई। पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रहनी चाहिये। उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान गोपनीय रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार के लिये जिम्मेदार लोगों के साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिये। उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री की शिकायतों का जिक्र किया। ज्ञापन में अवैध शराब की बिक्री रोकने, शराब कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्यवाही करने, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और सूचना देने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने समेत 12 मांगें रखी। कांग्रेस नेताओं ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन में कमलेश सिंघई, प्रवीण पस्तोर, निर्भय सिंह ठाकुर, शशि मोहन तिवारी, सुरेश तिवारी, नरेंद्र सिंह ठाकुर, जगदीश पाराशर, पीयूष तिवारी, राजाराम अहिरवार, अशोक परिहार, प्रमोद राय समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सहोदया सिंगिंग प्रतियोगिता में डीपीएस मकरोनिया द्वितीय

सागर, देशबन्धु। सेंट मैरी स्कूल में आयोजित सहोदया सिंगिंग प्रतियोगिता में दिल्ली पब्लिक स्कूल मकरोनिया के विद्यार्थियों ने शानदार गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुये द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में सागर शहर के 13 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सहभागिता की, डीपीएस मकरोनिया के विद्यार्थियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मधुर गायन और प्रभावशाली प्रस्तुति देकर निर्णायक मंडल एवं दर्शकों को प्रभावित किया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय का गौरव बढ़ा। विद्यालय के प्राचार्य जिजीष जोसेफ एवं संगीत शिक्षक सुदीप ताम्रकार ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुये कहा कि संगीत विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति को निखारने का सशक्त माध्यम है। विद्यालय प्रबंधन ने प्रतिभागी विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुये उन्हें भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिये प्रेरित किया।

अवैध शराब बिक्री के आरोपों को लेकर महिलाओं ने थाना प्रभारी को सौंपा शिकायत पत्र

गौरझामर, देशबन्धु। ग्राम बरकोटी क्षेत्र में कथित अवैध शराब बिक्री को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने थाना प्रभारी को शिकायत पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों ने क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री किये जाने का आरोप लगाते हुये मामले की जांच कराने तथा दोषी पाये जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब कारोबार की शिकायतें सामने आती रही हैं। इस संबंध में पूर्व में भी पुलिस को मौखिक एवं लिखित रूप से जानकारी दिये जाने की बात कही गई, लेकिन अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने, मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। शिकायत पत्र सौंपने वालों में सरोजरानी, राधारानी सेन, आशाबाई, शीलरानी, सुमतरानी सहित बड़ी संख्या में महिलायें शामिल रही।

विद्यार्थियों में कौशल विकास ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है: डॉ. सरोज

सागर, देशबन्धु। पं. दीनदयाल उपाध्याय शास. कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में अल्पकालिक रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिये तैयार किया जा रहा है। योजनाबद्ध अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को कपड़े के बैग निर्माण, सिलाई एवं डिजाइनिंग, व्यक्तित्व विकास तथा पारंपरिक लोक नृत्य जैसी विविध विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थी उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुये नई-नई तकनीक एवं कौशल सीख रहे हैं। इन बहुआयामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों की अंतर्निहित प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारना, कौशल क्षमता का विकास करना तथा उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाना है। विशेष रूप से कपड़े के बैग निर्माण का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को रचनात्मकता के साथ-साथ उपयोगी उत्पाद तैयार करने की दक्षता प्रदान कर रहा है। वही व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मविश्वास, संवाद कौशल एवं प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। पारंपरिक लोक नृत्य के प्रशिक्षण से विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक विरासत और लोक कलाओं से भी जुड़ रहे हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरोज गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में संचालित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में नया आत्मविश्वास एवं सीखने की ललक देखने को मिल रही है। डॉ. गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों में कौशल विकास ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है। किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक एवं हुनर आधारित शिक्षा आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उन्हें ऐसे कौशल से जोड़ना आवश्यक है, जिनके माध्यम से वे अपने लिये रोजगार के अवसर तलाश सकें और आवश्यकता पड़ने पर स्वरोजगार भी स्थापित कर सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं रोजगारपरक क्षमता को बढ़ावा देने के लिये भविष्य में भी ऐसे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभारी डॉ. प्रतिभा जैन द्वारा विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम के संचालन में महाविद्यालयीन स्टाफ एवं स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की पूरी टीम का सक्रिय सहयोग बना हुआ है।

देशबन्धु
सागर, गुरुवार, 10 सितम्बर 2026
संस्थापक-संपादक : स्व. मायाराम सुरजन

नस्लीय नफरत का शिकार समाज

भारत जैसे उदार समझे जाने वाले देश में नफरत को इस कदर बढ़ावा दिया जा चुका है कि आम जनता के बीच से ही कुछ लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने में नहीं झिझक रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते दिन मणिपुर के चर्चित गिटारिस्ट और संगीत शिक्षक चोंगथाम विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला इसका ताजा उदाहरण है। चोंगथाम विक्रम सिंह का कसूर केवल इतना था कि उन्होंने अपने घर के पास शोर मचा रहे कुछ लोगों को टोका। हो सकता है टोकने का यह मामला हत्या तक नहीं पहुंचता, लेकिन चोंगथाम विक्रम सिंह का पूर्वोत्तर से होना क्या इस हत्या का एक अहम कारक बना है, इस सवाल पर गंभीरता से सोचना होगा। राज्य और केंद्र की सत्ता पर बैठी भाजपा सरकार ने तो इसमें नस्लीय नफरत के नजरिए तो फौरन खारिज कर दिया है। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू, जो खुद पूर्वोत्तर से आते हैं, का कहना है कि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, चोंगथाम विक्रम सिंह पूर्वोत्तर से हैं, ऐसा न देखकर ये देखना चाहिए कि वे भारतीय थे।

ऐसी बात सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगती है और कायदे से होना भी यही चाहिए, लेकिन किरण रिजिजू को ईमानदारी से बताना चाहिए कि क्या मोदी सरकार में ऐसा ही होता है। क्योंकि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पूर्वोत्तर के लोगों को लगातार नस्लीय हिंसा या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। उत्तराखंड में ही पिछले साल 9 दिसंबर को त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा को चाइनीज़ और मोमो जैसे अपमानजनक शब्द कहते हुए पीट-पीट कर मार दिया गया था। इसलिए, विक्रम सिंह मामले में यह पड़ताल भी करनी ही चाहिए कि इसके पीछे नस्लीय हिंसा थी या नहीं।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दुखद मौत के लिए जिम्मेदार हमले की घटना से हम लोग बहुत परेशान हैं। इस घटना ने राजधानी में उत्तर-पूर्वी लोगों द्वारा झेली गई क्रूरता के दर्दनाक घावों को एक बार फिर से हरा कर दिया है। इसी तरह मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से गहन जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी समेत सामने आ रहे सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ तेजी से उचित कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित को जल्द न्याय मिलना चाहिए। क्या भाजपा इन लोगों के बयानों को भी राजनीति बताएगी, क्योंकि ये तो एनडीए नेताओं के ही बयान हैं।

वैसे ऐसी हरेक घटना पर राहुल गांधी की बात ही याद आती है कि नफरत का केरोसिन छिड़का जा चुका है और चिंगारी लगाने की देर है। कुछ वक्त पहले तक शायद इस चिंगारी को सुलगाने वाले लोगों को कानून का कुछ डर तो रहता ही होगा, लेकिन अब ये बेखौफ आग लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे आपराधिक तत्व कहीं न कहीं आश्वस्त हैं कि सत्ता में बैठे लोग उन्हें बचा ही लेंगे। दिल्ली में एक दलित को पीटने वाले स्वतंत्र भारद्वाज ने यही कहा था कि उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी, क्योंकि मोदीजी उसके बड़े भाई हैं। देश में अब हर गली-कूचे में स्वतंत्र भारद्वाज जैसे लोगों का बढ़ जाना समाज के लिए काफी चिंताजनक है। क्योंकि अब बात केवल हिंदू-मुसलमान, दलित-स्वर्ण तक सीमित नहीं रही, समूचे समाज को यह नफरत लील रही है।

गौरतलब है कि 54 वर्षीय चोंगथाम विक्रम सिंह पिछले 17 वर्षों से दिल्ली में संगीत सिखाने का काम कर रहे थे। उन्हें मणिपुर के संगीत जगत में एक चर्चित गिटारिस्ट और पश्चिमी संगीत के प्रमुख कलाकारों में गिना जाता था। रविवार रात करीब 11:30 बजे उन के घर के पास कुछ लोग शोर-शराबा कर रहे थे। इनमें आसपास के ढाबों में काम करने वाले डिलीवरी और पैकेजिंग कर्मचारी भी शामिल थे। चोंगथाम विक्रम सिंह ने उन लोगों से शोर मचाने से मना किया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि सिंह अपने घर की ओर भागे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया और इमारत की तीसरी मंजिल तक पहुंचकर उनके साथ उनको बेरहमी से पीटा। उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने सात लोगों को हिरासत में तो लिया है, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार समेत पूर्वोत्तर के लोगों को नाइंसाफी की आशंका है। यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या गिरफ्तारी के साथ-साथ पूर्वोत्तर के नागरिकों की सुरक्षा और नस्ली भेदभाव से जुड़ी व्यापक समस्या पर भी सरकार ठोस कार्रवाई करेगी? क्योंकि अब तक ऐसी कोई मिसाल मोदी सरकार ने नहीं दी है।

नरेन्द्र मोदी को अपने प्रचार कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक पिता की अपने ही घर के बाहर, देश की राजधानी में हत्या कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी कई घटनाओं के बाद दिल्ली में रहने वाला पूर्वोत्तर का हर परिवार आज खुद से पूछ रहा है- 'क्या हम यहां सुरक्षित हैं?' राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए, क्या कर रहे हैं, खासकर पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ? तत्काल जांच होनी चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

राहुल गांधी तो अपनी जवाबदेही निभा रहे हैं, सरकार कब काम करना शुरु करेगी इसका इंतजार है।

सिमोन द बुवा के देश में नारी उत्पीड़न

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

20वीं सदी के फ्रांस में वैश्विक नारीवाद की अहम किरदार थीं- सिमोन द बुवा। नारी सशक्तीकरण पर उनके मौलिक और क्रांतिकारी विचारों पर दुनिया में आज भी मंथन होता है। सिमोन द बुवा की सुप्रसिद्ध किताब है 'द सेकंड सेक्स'। इस किताब में सिमोन कहती हैं कि औरत पैदा नहीं होती है, बल्कि समाज औरत को गढ़ता है। वह बार-बार इस पर ज़ोर देती हैं कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, लड़कियों को मजबूर करता है 'स्त्री' बनने के लिए। सिमोन का कहना है कि इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि हमारे धर्म में औरतों की भी पूजा होती है। धर्म तो वास्तव में आदमियों के द्वारा बनाया हुआ एक तरीका है औरतों पर शासन करने का।

फ्रांस ने दुनिया को केवल सिमोन द बुवा जैसी अद्‌भुत नारीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं दी, बल्कि उनसे पहले फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अद्‌भुत विचार दुनिया को दिया। यही लोकतंत्र की नींव बना और भारत के संविधान की बुनियाद भी इसी पर टिकी है। अब इसी फ्रांस में मानवता के लिए जरूरी इन मूल्यों पर कुठाराघात करने का काम किया है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्था यानी बीएपीएस ने। पाठकों को बता दूं कि गुजरात के बोचासन से इस संस्था का संबंध है। अक्षरधाम मंदिर इसी संस्था का है। हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बीएसपीएस के एक मंदिर का उद्‌घाटन हुआ। जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हार्दिक खुशी जाहिर की थी।

इस संस्था के कहां कितने मंदिर बनते हैं यह अलग मुद्दा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस संप्रदाय में महिला से दूरी बनाए रखने, महिला के साथ अकेले में बात न करने आदि के नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन इससे जुड़े लोग करते हैं। यह भी उनका निजी मामला है कि वे महिला से बात करें न करें। लेकिन पेरिस में मंदिर उद्‌घाटन के लिए संस्था का जो प्रतिनिधि मंडल पेरिस गया था, उसमें करीब 100 लोग एफिल टावर देखने पहुंचे तो उनके कहने पर वहां पहले बाकायदा महिला कर्मचारियों को हटाया गया।

एफिल टावर की कर्मचारी यूनियन की प्रतिनिधि डायने डावोइन के अनुसार, जब प्रतिनिधि मंडल टावर के अंदर से गुजर रहा था, तब महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों से हटने के लिए कहा गया ताकि उनकी जगह पुरुष कर्मचारी खड़े हो सकें। कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ महिलाओं को अपनी पोस्ट छोड़कर दूसरे हिस्सों में जाने के लिए कहा गया, जबकि कुछ स्थानों पर उनकी जगह पुरुष कर्मचारियों को तैनात किया गया। महिला कर्मचारियों को प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी के दौरान कुछ खास इलाकों में जाने या उन्हें पार करने से भी रोका गया।

> **जिस फ्रांस में सिमोन द बुवा ने पुरुष और स्त्री समानता की मशाल बुलंद की, धार्मिक व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई, उसी फ्रांस में सौ साल बाद लैंगिक भेदभाव की ऐसी घटना घटेगी, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। इस घटना से आहत एफिल टावर के कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया, जिसके चलते टावर को आगंतुकों के लिए बंद रखना पड़ा।**

जिस फ्रांस में सिमोन द बुवा ने पुरुष और स्त्री समानता की मशाल बुलंद की, धार्मिक व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई, उसी फ्रांस में सौ साल बाद लैंगिक भेदभाव की ऐसी घटना घटेगी, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। इस घटना से आहत एफिल टावर के कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया, जिसके चलते टावर को आगंतुकों के लिए बंद रखना पड़ा। गौरतलब है कि एफिल टावर दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और इसकी वेबसाइट के अनुसार यहां हर साल करीब 70 लाख लोग आते हैं। फिलहाल पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगोआर ने मामले की जांच कराने की घोषणा की है। जबकि एफिल टावर का संचालन करने वाली कंपनी एसईटीई ने माना कि हिंदू प्रतिनिधि मंडल की ओर से महिलाओं के साथ बातचीत या संपर्क को सीमित रखने की मांग की गई थी। कंपनी ने कहा कि ऐसी शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। एसईटीई के अध्यक्ष एरियल वेल ने इसे अस्वीकार्य बताया और कहा कि एफिल टावर फ्रांस के गणतांत्रिक मूल्यों तथा महिला और पुरुषों की समानता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था उसके मूल्यों और लैंगिक समानता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी तथा मामले में जांच की जाएगी। वहीं फ्रांस की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष याएल ब्राउन-पिवे ने भी घटना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों की मांग पूरी करने के लिए महिलाओं को पीछे हटने या सार्वजनिक जीवन से 'अदृश्य' होने के लिए नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि दूसरे लोगों का स्वागत करने का अर्थ यह नहीं है कि फ्रांस अपने मूल्यों से समझौता करे।

फ्रांस की समानता मंत्री ऑरोर बर्जे ने भी कहा कि फ्रांस में महिलाओं से खुद को 'मिटा देने' या पीछे हटने के लिए नहीं कहा जाता और कोई भी धार्मिक विचार गणराज्य के कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता।

फ्रांसीसी सरकार को यह देखने की भी जरूरत है कि उनके भीतर ऐसे कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने महिला से दूर रहने जैसे संकीर्णतावादी विचार को बढ़ावा देने में मदद की।

बीएपीएस का तो कहना है कि उसका प्रतिनिधि मंडल बड़ा था, इसलिए उसने एफिल टावर में व्यवस्था को बदलने कहा, लेकिन उसमें लैंगिक भेदभाव की बात नहीं थी। लेकिन जब टावर संचालन करने वाली कंपनी ही मान रही है कि बीएसपीएस की शर्तों को नहीं मानना चाहिए था, तो जरूर कहीं न कहीं लैंगिक भेदभाव हुआ ही होगा। बहरहाल फ्रांस तो इस मामले की जांच अपनी तरह से कर ही लेगा और जिस देश की बुनियाद उदार मानवतावादी मूल्यों पर पड़ी हो, वह खुद को दुरुस्त कर भी लेगा। लेकिन भारत इस वैश्विक शर्मिंदगी से कब और कैसे उबरेगा, यह एक बड़ा सवाल है।

बीएसपीएस का मंदिर पेरिस में बना तो नरेन्द्र मोदी ने इसे ग्रेट जॉय बताया था, तो क्या इस घटना के बाद उन्हें ग्रेट शेम महसूस नहीं हुई। क्योंकि बीएपीएस से उनकी नजदीकी बरसों पुरानी है। मोदी का वैवाहिक जीवन कैसा रहा और शादीशुदा होने के बावजूद वे अकेले क्यों रहते हैं, यह उनका निजी मामला है। लेकिन वैश्विक स्तर पर जब एक भारतीय धार्मिक संस्था पर महिलाविरोधी होने के आरोप लगते हैं, तो बतौर प्रधानमंत्री क्या उन्हें बीएपीएस से अपने संबंधों को स्पष्ट नहीं करना चाहिए।

वैसे बीएपीएस को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर उन्हें महिलाओं से तकलीफ है, उन्हें देखना भी उनके नियमों में गवारा नहीं है, तो फिर दुनिया भर में मंदिर बनवाने निकले ही क्यों हैं। दुनिया से महिलाओं को तो गायब नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये पूरा प्रतिनिधि मंडल चार्टर्ड फ्लाइट से पेरिस गया हो, जिसमें परिचारक ही रहे हों, परिचारिकाएं नहीं। लेकिन फिर वे पेरिस में मंदिर बनवा कर उसी फ्लाइट से भारत वापस आ जाते, उन्हें एफिल टावर या किसी भी विश्वप्रसिद्ध स्थल को देखने की जरूरत ही क्या है।

हमेशा की तरह इस बार भी इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं आया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद को सही अर्थों में रबर स्टैम्प ही बना दिया है, जो केवल मोदी सरकार के हर फैसले, हर बात पर मुहर लगाती है। याद कीजिए कि जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था तो भाजपा ने इस बात का बड़ा श्रेय लिया था उसके शासन में देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली है। लेकिन उनकी आदिवासी या महिला पहचान से देश में इन वर्गों की वस्तुस्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी सरकार में दलित, आदिवासी, मुसलमान, और महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कभी ऐसी घटनाओं पर सार्थक हस्तक्षेप किया हो, याद नहीं पड़ता।

असलियत से ज़्यादा गणितीय हो सकती है भारत की तेज़ विकास दर

■ नन्तू बनर्जी

ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव, क्षेत्रीय आपूर्ति में रुकावट, कम निवेश और बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। ऐसे में, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत की रिकॉर्ड वास्तविक जीडीपी विकास दर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। आर्थिक नज़रिए से भारत में वित्त वर्ष की पहली तिमाही को आम तौर पर 'धीमी विकास वाला समय' माना जाता है। देश की आधिकारिक आर्थिक विकास दर ने पहली बार एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक विवाद खड़ा कर दिया है। जीडीपी की तेज़ विकास घरेलू निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने जैसे कमज़ोर संकेतकों को नहीं दिखाती है। यह ज़मीनी हकीकत को भी नहीं दिखाती है, जैसे कि ऊर्जा और खाद की ज़्यादा कीमतें, जो लगभग सभी सामान, औद्योगिक उत्पादों और लोगों की खपत की कीमतों पर असर डाल रही हैं। महंगाई को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर'- खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नकारात्मक डिफ्लेटर - ने असली महंगाई को कम करके दिखाया है। आम नज़रिए से, बताई गई तेज़ आर्थिक विकास दर असलियत में ज़्यादा गणितीय लग सकती है।

देश की वास्तविक जीडीपी विकास दर दुनिया के रूझान के बिल्कुल उलट है। ओईसीडी ग्लोबल इकानॉमिक आउटलुक के विस्तृत अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, दुनिया की आर्थिक विकास दर 2026 में धीमी होकर अनुमानित 2.6 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत हो रही है, जो पिछले सालों की तुलना में कम है। यह सुस्ती मुख्य रूप से ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव, क्षेत्रीय आपूर्ति में रुकावट, कम निवेश और बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों के कारण है। ये कारक आम तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहे हैं। इस साल दुनिया की आर्थिक विकास दर पर मुख्य दबाव ऊर्जा के झटकों, बढ़ते व्यापार अवरोधों और ज़्यादा कर्ज़ और उधार का है। भू-राजनीतिक संघर्षों ने, खासकर पश्चिम एशिया में, ईंधन और गैस की आपूर्ति को कम कर दिया है, जिससे सभी स्तरों पर उत्पादन और खपत की लागत बढ़ गई है और महंगाई को बढ़ावा मिला है। एकतरफा टैरिफ उपायों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बिखराव ने सामान के व्यापार की मात्रा के अनुमानों को कम कर दिया है। उधार लेने की ज़्यादा लागत राजकोषीय गुंजाइश को सीमित कर रही है, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, मार्च 2026 के आखिर में भारत का कुल विदेशी कर्ज़ 762.8 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 26.3 अरब ज़्यादा है। इससे कर्ज़-जीडीपी अनुपात 20.8 प्रतिशत हो गया, जो कुल विदेशी देनदारियों में बढ़ोतरी को दिखाता है।

ऊंची ब्याज दरों और व्यापार में बदलावों की वजह से अमेरिकी जीडीपी की विकास दर धीमी होकर लगभग 1.5-2.0 प्रतिशत रह गई है। ऊर्जा पर ज़्यादा निर्भरता और स्थानीय औद्योगिक रुकावटों के कारण यूरो क्षेत्र की आर्थिक विकास दर 0.5 से 1.3 प्रतिशत के आसपास सुस्त बनी हुई है। घरेलू संरचनात्मक बदलावों के बीच चीन की अर्थव्यवस्था की रफ़्तार धीमी होकर लगभग 4.5-4.6 प्रतिशत हो गई है। मौजूदा साल में, दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाएं -अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और यूके - 2.5 प्रतिशत से कम की बहुत धीमी रफ़्तार से आगे बढ़ रही हैं, जबकि छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 प्रतिशत की मज़बूत वास्तविक जीडीपी दर दिखा रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी को 81.36 लाख करोड़ आंका, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 75.46 लाख करोड़ था। इससे 7.8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर मिली, जो रिज़र्व बैंक के 2026-27 के लिए 6.7 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है।

स्वतंत्र विश्लेषक और आलोचक बताते हैं कि आधार वर्ष बदलने, पुराने डेटा में संशोधन करने और पुराने आंकड़ों को नए इंडेक्स तरीकों के साथ मिलाने से साल-दर-साल प्रतिशत के नतीजों में बढ़ोतरी दिख सकती है। कुछ वैकल्पिक व्याख्याओं का तर्क है कि अगर पुराने या बेमेल आधार समायोजन को हटा दिया जाए, तो कुछ खास सब-सेगमेंट में वास्तविक विकास दर कम दिखती है। हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि सेवा और हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र उत्साहजनक रफ़्तार दिखा रहे हैं, जबकि प्राथमिक कृषि और ग्रामीण सेक्टर अपेक्षाकृत सुस्त बने हुए हैं (तीन प्रतिशत से कम की विकास दर के साथ)। वास्तविक रूप में सकल जमा पूंजी के निर्माण में 11.9 प्रतिशत की तेज़ी आई, जो तेज़ी से क्षमता बढ़ाने, निजी पूंजीगत व्यय और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर लगातार खर्च का संकेत है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसमें बिजली और परिवहन उपकरण के क्षेत्र में हुई भारी बढ़त का अहम योगदान रहा। तृतीयक सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जिसमें वित्तीय, जमीन जायदाद, आईटी और पेशेवर सेवाओं (जो 12.1 प्रतिशत की दर से बढ़ीं) की बड़ी भूमिका रही। निजी अंतिम उपभोग खर्च में 7.1 प्रतिशत की स्थिर वास्तविक वृद्धि बनी रही, जिससे घरेलू बाजार बाहरी वैश्विक चुनौतियों के असर से बचा रहा।

भारत ने अपने जीडीपी के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। इसके साथ ही, जीएसटी, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और अनिगमित क्षेत्र के उद्यम के सालाना सर्वेक्षण जैसे आधुनिक आंकड़ा स्रोतों को शामिल किया गया है और 'डबल डिफ्लेशन' की पद्धति अपनाई गई है।

इन बड़े बदलावों का मकसद तेज़ी से डिजिटल और औपचारिक हो रही अर्थव्यवस्था को समझना है, हालांकि जब तक पुरानी श्रृंखला के आंकड़े नहीं आ जाते, तब तक पुराने आंकड़ों से तुलना करना मुश्किल होगा। आंकड़ा श्रृंखला में बदलाव के मुख्य कारणों में आधार वर्ष बदलना, नया आंकड़ा शामिल करना और तरीकों में सुधार करना शामिल है। आधार वर्ष को 2022-23 करने से अर्थव्यवस्था में हाल के संरचनात्मक बदलाव, खपत में बदलाव और कीमतों के सापेक्ष महत्व का पता चलता है। हाई-फ्रीक्वेंसी और बारीक डेटासेट को शामिल करने में जीएसटी रिटर्न, अनिगमित क्षेत्र सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और ई-वाहन रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें शामिल हैं। तरीकों में सुधार के लिए आपूर्ति और उपयोग तालिका फ्रेमवर्क, तिमाही आंकड़ों के लिए आनुपातिक डेंटन बेंचमार्किंग और इनपुट लागत को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और कृषि में डबल डिफ़्लेशन जैसे तरीके अपनाए गए हैं। इन सबके कारण पुराने और अप्रचलित तरीकों के बजाय सीधे सर्वे डेटा के ज़रिए अनौपचारिक और डिजिटल/गिग अर्थव्यवस्था के हिस्सों को बेहतर ढंग से दिखाया जा सका है। जब तक आधिकारिक पुराने आंकड़े की नयी श्रृंखला प्रकाशित नहीं हो जाती, तब तक सीधी तुलना नहीं की जा सकती।

फिर भी, यह सोचना गलत है कि 2026 में भारत के आयात और निर्यात पर वैश्विक व्यापार और आर्थिक चुनौतियों का बहुत कम असर पड़ेगा। वैश्विक चुनौतियां—जैसे पश्चिम एशिया में संघर्ष, शिपिंग रूट में रुकावट, माल ढुलाई और ऊर्जा की बढ़ती लागत, और टैरिफ़ नीतियों में बदलाव—भारत के बाहरी क्षेत्र पर दबाव डाल रही हैं, व्यापार घाटे को बढ़ा रही हैं और प्रमुख क्षेत्र में निर्यात की विकास दर को रोक रही हैं। घरेलू खपत बढ़ने और आयात बिल में भारी बढ़ोतरी के कारण देश का वस्तु व्यापार घाटा बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और ज़रूरी शिपिंग रूट के आसपास सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण माल ढुलाई की दरें, बीमा खर्च और ऊर्जा आयात की लागत बढ़ गई है। कृषि, टेक्सटाइल और रत्न व आभूषण जैसे पारंपरिक श्रम-प्रधान निर्यात सेक्टर में पश्चिमी देशों से कम मांग, सुरक्षात्मक टैरिफ़ में बदलाव और व्यापारिक तनाव के कारण साफ़ तौर पर सुस्ती देखी जा रही है। रुपये के कमज़ोर होने और अमेरिका के अलावा अन्य बाज़ारों में विविधता लाने की रणनीतियों के कारण वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त निर्यात में समय-समय पर सुधार देखा गया है। फिर भी, पूरे साल जीडीपी विकास दर को पहली तिमाही के ऊंचे स्तर पर बनाए रखना बहुत मुश्किल लग रहा है।

> **स्वतंत्र विश्लेषक और आलोचक बताते हैं कि आधार वर्ष बदलने, पुराने डेटा में संशोधन करने और पुराने आंकड़ों को नए इंडेक्स तरीकों के साथ मिलाने से साल-दर-साल प्रतिशत के नतीजों में बढ़ोतरी दिख सकती है। कुछ वैकल्पिक व्याख्याओं का तर्क है कि अगर पुराने या बेमेल आधार समायोजन को हटा दिया जाए, तो कुछ खास सब-सेगमेंट में वास्तविक विकास दर कम दिखती है। हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि सेवा और हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र उत्साहजनक रफ़्तार दिखा रहे हैं।**

आपके पत्र

हादसों के शिकार पढ़ने वाले बच्चे ही क्यों?

दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं यह उन लाखों सपनों की राजधानी भी है, जिन्हें लेकर देश के कोने-कोने से बच्चे, युवा और उनके परिवार यहां आते हैं। कोई आईएएस बनने का सपना लेकर आता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने का। कोई छोटे से गांव से चलकर दिल्ली की किसी कोचिंग की सीढ़ियां चढ़ता है और कोई अपने माता-पिता की वर्षों की बचत लेकर एक छोटे-से कमरे में अपना भविष्य खोजता है। लेकिन विडंबना देखिए,जिस दिल्ली में ये बच्चे भविष्य बनाने आते हैं, वही दिल्ली बार-बार उनके वर्तमान को छीन लेती है।

सवाल अब केवल यह नहीं है कि दिल्ली में हादसे क्यों होते हैं। असली सवाल यह है कि बार-बार वही हादसे क्यों होते हैं और हर हादसे के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं जागती? कुव्यवस्था की भयावह तस्वीर हाल की सत्य निकेतन इमारत दुर्घटना ने फिर सामने रख दी। छात्र-आवास वाली बहुमंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की मृत्यु की रिपोर्ट सामने आई और अधिकांश पीड़ित विद्यार्थियों के होने से छात्र आवासों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठे।

सबसे पीड़ादायक बात यह है कि विद्यार्थी दिल्ली में केवल पढ़ाई की फीस नहीं देते। वे कमरा किराये पर लेते हैं, भोजन के लिए भुगतान करते हैं, परिवहन का खर्च उठाते हैं और अपने परिवारों की आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक कीमत पर अपने सपनों को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो क्या उन्हें बदले में केवल असुरक्षित कमरे मिलेंगे? क्या उनके लिए अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा, आपातकालीन निकास और स्वच्छ जलनिकासी जैसी सुविधाएं विलासिता हैं?

राजधानी में पढ़ने वाले विद्यार्थी नागरिक नहीं हैं क्या? दिल्ली की प्रशासनिक समस्या का एक और गंभीर पहलू है जिम्मेदारी का बिखराव। नगर निगम, पुलिस, अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन कई संस्थाएं अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी अक्सर किसी एक छोटे कर्मचारी या किसी संचालक पर जाकर रुक जाती है।

हाल की प्रशासनिक जांचों के संबंध में रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि कई त्रासदियों में प्रणालीगत खामियां और प्रशासनिक लापरवाही चिन्हित हुईं, जबकि कार्रवाई अक्सर निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रही। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। यदि किसी इमारत को वर्षों तक नियमों के विरुद्ध चलने दिया गया, तो केवल चौकीदार या कनिष्ठ कर्मचारी दोषी कैसे हो सकता है?

लेकिन प्रश्न फिर वही है—यदि इतनी बड़ी संख्या में संस्थान नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो हादसे से पहले प्रशासन कहां था?

-संजीव ठाकुर

ललित सुरजन की कलम से

भाषण और आंकड़ों से परे

'छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने पंचायत शिक्षकों का संविलियन कर शिक्षकों का स्थायी कैडर निर्मित करने का फैसला लिया है। कुछ ऐसा ही फैसला मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लिया है। मेरा शुरू से मानना रहा है कि जब तक स्कूलों में पूर्णकालीन और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। वर्ल्ड बैंक के इशारे पर स्थायी शिक्षकों का कैडर धीरे-धीरे कर पूरे देश में समाप्त कर दिया गया। इससे शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिला। आज अगर वह स्थिति बदलती है तो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस बारे में एक समन्वित दीर्घकालीन नीति बनाकर लागू करना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी विसंगतियां व्याप्त हैं। उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ-साथ शाला भवन, उपकरण, पुस्तकालय, खेल का मैदान, इन सब पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। दिल्ली का मॉडल यहां शायद काम आ सकता है!'

(देशबन्धु में 05 जुलाई 2018 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2017/08/blog-post_9.html

आज पोला अमावस्या

अन्नदाता और उसके सहचर बैलों के सम्मान का पर्व

भाद्रपद अमावस्या भारतीय धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवसर पर स्नान, दान, पितरों का स्मरण और तर्पण जैसे धार्मिक कर्म किए जाते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में इस अमावस्या के अलग नाम और अलग लोकाचार दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी अमावस्या का लोकजीवन से जुड़ा रूप पोला के रूप में सामने आता है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि एक ही तिथि धार्मिक आस्था, कृषि जीवन और लोकसंस्कृति के अनेक रंगों को अपने भीतर समेट लेती है।

भाद्रपद अमावस्या पर जीवंत होती है छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति। छत्तीसगढ़ की पहचान केवल उसकी हरियाली, नदियों, जंगलों और खनिज संपदा से नहीं है, बल्कि उसकी समृद्ध लोकपरंपराओं और तीज-त्योहारों से भी है। यहां के पर्व प्रकृति, कृषि, पशुधन और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध को अभिव्यक्त करते हैं। इन्हीं लोकपर्वों में पोला अथवा पोरा तिहार का विशेष स्थान है। भाद्रपद अमावस्या के अवसर पर मनाया जाने वाला यह पर्व मूलत: किसान और उसके सबसे विश्वसनीय कृषि-सहचर बैल के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और आत्मीयता का पर्व है।

आज खेती के तौर-तरीके बदल रहे हैं। ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि उपकरणों ने बैलों पर निर्भरता काफी कम कर दी है। शहरों में रहने वाली नई पीढ़ी के लिए बैल अब कृषि जीवन के प्रत्यक्ष सहभागी के बजाय स्मृति और लोकसंस्कृति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन इससे पोला का महत्व समाप्त नहीं होता। बल्कि आज इस पर्व का संदेश और अधिक व्यापक हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य अकेले विकास नहीं कर सकता। उसके जीवन और सभ्यता के निर्माण में प्रकृति, पशु-पक्षियों और असंख्य जीवों का योगदान रहा है।

पोला पर्व का संबंध केवल बैलों से ही नहीं, बल्कि खेती और फसल से भी है। लोकमान्यता है कि इसी समय धान की बालियों में दूध भरना प्रारंभ होता है और अन्नमाता गर्भ धारण करती हैं। किसान के लिए यह आने वाली फसल और समृद्धि की आशा का अवसर होता है। इसलिए पोला वास्तव में प्रकृति, कृषि, पशुधन और किसान इन चारों के बीच स्थापित उस जीवनचक्र का उत्सव है, जिसके आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सदियों से आगे बढ़ती रही है।

पोला की सबसे सुंदर विशेषताओं में बच्चों की भागीदारी भी है। ग्रामीण अंचलों में मिट्टी अथवा लकड़ी से बने छोटे-छोटे बैल, चूल्हा, चक्की, चुकिया और अन्य खिलौने तैयार किए जाते हैं। बच्चे उन्हें सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह परंपरा केवल मनोरंजन नहीं है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी को बचपन से ही यह सीख मिलती है कि पशु हमारे जीवन और कृषि व्यवस्था के महत्वपूर्ण साथी हैं। लोकपर्व इस प्रकार बिना किसी औपचारिक पाठशाला के बच्चों को अपनी मिट्टी, संस्कृति और परंपरा का पाठ पढ़ाता है।

पोला केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि पारिवारिक उल्लास और सामुदायिक मेल-मिलाप का अवसर भी है। घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी खान-पान की समृद्ध परंपरा के अनुरूप ठेठरी, खुरमी सहित अनेक व्यंजन इस अवसर पर तैयार किए जाते हैं। बहन-बेटियों के मायके आने, परिवार के साथ समय बिताने और रिश्तों में स्नेह बढ़ाने की परंपरा भी इस पर्व को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है।

-सुरेश सिंह बैस 'शाश्वत'

सार-समाचार

राज्यपाल से मनोनीत मुख्य न्यायाधीश कोगजे ने की सौजन्य भेंट

भोपाल, देशबन्धु। राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे ने बुधवार को लोकभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल श्री पटेल का उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री कोगजे की पत्नी अर्चना अल्पेश कोगजे उनके साथ थीं। इससे पूर्व लोकभवन आगमन पर मनोनीत मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे का अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी उपस्थित थे।

संदीप ने महिला एवं बाल विकास आयुक्त का कार्यभार संभाला

भोपाल, देशबन्धु। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संदीप जी.आर. ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया। राज्य शासन द्वारा उन्हें इस विभाग के अपर सचिव तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का दायित्व भी सौंपा गया है। संदीप वर्ष 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे छतरपुर एवं सागर जिले के कलेक्टर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। सागर कलेक्टर के रूप में उन्होंने प्रशासन में तकनीक के प्रभावी उपयोग, जनभागीदारी और नवाचार को प्राथमिकता देते हुए कई अभिनव पहल कीं।

प्रधान आरक्षक भर्ती प्रायोगिक परीक्षा 27 को

भोपाल, देशबन्धु। मध्यप्रदेश पुलिस में प्रधान आरक्षक कम्प्यूटर एवं सहायक उप निरीक्षक कम्प्यूटर भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 27 सितम्बर 2026 को मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में आयोजित की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र एवं परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं।

विजयादशमी से शुरू होगी दिग्विजय की स्वाभिमान यात्रा,

भोपाल, देशबन्धु। दिग्विजय सिंह ने धर्म और आस्था के नाम पर कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' की घोषणा की है। यात्रा 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर उज्जैन से अयोध्या तक निकलेगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, सत्य, श्रद्धा और सामाजिक सद्भाव बढ़ाना है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि यह यात्रा धर्म के नाम पर लूट और श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ के खिलाफ है। उन्होंने विजयादशमी के दिन उज्जैन से अयोध्या तक इसे निकालने का निर्णय लिया है।

दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के नाम पर पारदर्शिता, सत्य और श्रद्धा की रक्षा करना है। साथ ही सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है।

दुबई के निवेशकों को भाया मध्य प्रदेश : 53 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैश्विक उद्योग जगत को दिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 का न्योता

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छह से आठ सितंबर तक के दुबई दौरे में प्रदेश को 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। एआईएम कांग्रेस-2026 के मंच से मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की निवेश क्षमता और नई औद्योगिक नीतियों को दुनिया के सामने रखते हुए निवेशकों को प्रदेश आने का न्योता दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश का लक्ष्य केवल पूंजी आकर्षित करना नहीं, बल्कि निवेश के साथ तकनीक, बाजार, निर्यात और रोजगार को जोड़ना है। उन्होंने प्रदेश को वैश्विक कंपनियों के लिए दीर्घकालिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया। डीपी वर्ल्ड, शराफ ग्रुप, जेम्स एजुकेशन, राणा होल्डिंग्स, क्रिसेंट एंटरप्राइजेज, चोइथराम्स, वीएफएस ग्लोबल और बी-आह सहित कई वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश की संभावनाओं पर सीधे संवाद हुआ।

लॉजिस्टिक्स और तकनीक पर खास जोर

डीपी वर्ल्ड के साथ पवारखेड़ा में बहुआयामी लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। शराफ ग्रुप ने रेल-साइडिंग आधारित लॉजिस्टिक्स पार्क में 30 से 50 मिलियन डॉलर निवेश की संभावना जताई। जेम्स एजुकेशन ने प्रदेश के प्रमुख शहरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यालय और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में रुचि दिखाई।

राणा होल्डिंग्स के साथ स्मार्ट विनिर्माण, डेटा सेंटर, हरित हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, ई-मोबिलिटी और कृषि मशीनरी पर चर्चा हुई। क्रिसेंट एंटरप्राइजेज ने ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और शहरी अधोसंरचना में निवेश की संभावनाएं तलाशने की इच्छा जताई। चोइथराम्स समूह के साथ आधुनिक खुदरा बाजार, खाद्य प्रसंस्करण और किसानों से सीधे खरीद को बढ़ावा देने पर विचार हुआ।

यूएई से पर्यटन और विमानन सहयोग

यूएई ने मध्य प्रदेश में होटल और आतिथ्य क्षेत्र की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति जताई। मध्य प्रदेश और यूएई के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने पर भी सहयोग की दिशा में पहल हुई। विश्व बैंक के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शासन परियोजनाओं में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

शारजाह स्थित बी-आह के साथ कचरा प्रबंधन, कचरे से ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था में साझेदारी की संभावनाएं तलाशते हुए इंदौर के स्वच्छता और बायो-सीएनजी मॉडल को वैश्विक तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया गया।

समिट के लिए जुटाया समर्थन

दुबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने यूएई, तातारस्तान, इथियोपिया, अरब देशों और वैश्विक उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में भागीदारी का निमंत्रण दिया। शारजाह चैंबर के साथ प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और निर्यातकों को खाड़ी बाजार से जोड़ने की पहल भी की गई।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में पारदर्शी नीतियों, एकल खिड़की व्यवस्था और समयबद्ध सहयोग के माध्यम से निवेश को गति दी जा रही है।

दुबई दौरे में निवेश के बड़े प्रस्ताव

डीपी वर्ल्ड : पवारखेड़ा में बहुआयामी लॉजिस्टिक्स केंद्र, भंडारण और शीत-श्रृंखला विकसित करने की संभावनाएं।

शराफ ग्रुप : रेल-साइडिंग आधारित लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 30-50 मिलियन डॉलर निवेश की संभावना। करीब 300-600 रोजगार के अवसर।

जेम्स एजुकेशन : प्रमुख एवं उभरते शहरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यालय और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में रुचि।

राणा होल्डिंग्स : स्मार्ट विनिर्माण, डेटा सेंटर, हरित हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, ई-मोबिलिटी और कृषि मशीनरी में निवेश की संभावनाएं।

क्रिसेंट एंटरप्राइजेज : ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, सूचना प्रौद्योगिकी और शहरी अधोसंरचना में दीर्घकालीन निवेश पर चर्चा।

चोइथराम्स समूह : आधुनिक खुदरा बाजार, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और किसानों से सीधे खरीद की संभावनाएं।

बी-आह : ठोस कचरा प्रबंधन, कचरे से ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था और हरित गतिशीलता में तकनीकी साझेदारी।

विश्व बैंक : कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शासन परियोजनाओं में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की संभावनाएं।

यूएई : पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशने प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश आएगा। विमानन संपर्क बढ़ाने पर भी पहल।

तातारस्तान : उन्नत विनिर्माण, पेट्रोकेमिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, कृषि और लॉजिस्टिक्स में साझेदारी पर चर्चा।

वैश्विक बाजार में मध्य प्रदेश के उत्पाद : दुबई में चंदेरी, महेश्वरी, बैतूल बेल मेटल, उज्जैन बाटिक, भोपाल जरी-जरदोजी और ग्वालियर कालीन जैसे एक जिला-एक उत्पाद एवं भौगोलिक संकेतक उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग की गई।

लॉजिस्टिक्स, एआई, शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन बने आकर्षण के केंद्र

उप मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद चिकित्सा छात्रों का आंदोलन खत्म

स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत वृद्धि होगी

बल प्रयोग पर 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चिकित्सा छात्रों के स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गांधी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि छात्रों की इस मांग पर पहले से ही चर्चा चल रही थी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस विषय पर सतत संवाद कर रहे थे।

प्रतिनिधिमंडल ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त हुए आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और काम पर लौट आए। शुक्ल ने आंदोलन के पहले दिन छात्रों के साथ पुलिस द्वारा बल प्रयोग के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने युवा चिकित्सकों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा भाव और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने से चिकित्सकों को वास्तविक परिस्थितियों को समझने और व्यापक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कैंपस में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्र-छात्राओं पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। घटना में घायल छात्रों के समुचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

समन्वय से निकला समाधान

प्रशिक्षु, जूडा एवं एमटीए सहित विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय और संवाद स्थापित करने में विद्यार्थी परिषद, डॉ. हितेश वाजपेयी एवं एमटीए अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद और आपसी सहमति से पूरे प्रकरण का सौहार्दपूर्ण समाधान निकला। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सभी प्रतिनिधियों को सकारात्मक पहल के लिए बधाई दी। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल का आभार व्यक्त किया।

इंदौर में अतिक्रमण हटाने की दौरान हंगामा

एडिशनल डीसीपी को धक्का दिया, 6 हिरासत में

इंदौर, देशबन्धु। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के साउथ टोड़ा इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया। कुछ स्थानीय लोगों ने कथित अवैध निर्माणों को तोड़े जाने का विरोध किया, जिसके बाद मामला बढ़ गया। निगम की कार्रवाई के दौरान एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल को एक युवक ने धक्का दे दिया। धक्का लगने से वह जमीन पर गिर पड़े। पुलिस ने हंगामे के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि अतिक्रमण हटाने निगम की टीम पहुंची थी और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे। निगम की 100 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम कार्रवाई में जुटी थी। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार सुबह एक बडी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने साउथ तोड़ा क्षेत्र में कान्ह नदी किनारे बने 7 पक्के मकान और 45 कारखाने हटाए। ये सभी शासकीय भूमि पर बने हुए थे। कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस देकर लोगों से अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा था, बावजूद इसके जब अवैध निर्माण नहीं हटे तो कार्रवाई करना पड़ी, जबकि लोग कह रहे हैं कि उन्हें सामान हटाने का मौका तक नहीं दिया गया

रीवा में जच्चा-बच्चा की मौत का मामला

धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया

भोपाल, देशबन्धु। रीवा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव, पिछले दिनों महिला और उसके नवजात की मौत को अपराधिक लापरवाही बताते हुए विधायक अभय मिश्रा ने बुधवार को मंत्रालय के सामने धरना दिया। मिश्रा करीब आधा घंटे ही वहां बैठे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनकी मांग है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफा दें। धरने से पहले मिश्रा ने कहा कि रीवा के सरकारी अस्पताल में एक के बाद एक हो रही मौतों और इससे गुस्साए लोगों की पीड़ा यह दिखाती है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही का संकट है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कल्पना मिश्रा की मौत को कांग्रेस ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी रीवा पहुंचकर धरने में शामिल हो चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। अब सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने राजधानी में मोर्चा खोला तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

उमंग सिंघार ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप

रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को पुलिस द्वारा धरना स्थल से हिरासत में लिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे तानाशाही बताते हुए कहा है कि क्या एक जनप्रतिनिधि का न्याय मांगना भी इस सरकार में अपराध हो गया है? उन्होंने कहा कि भाजपा का यह तानाशाही रवैया और दमनचक्र अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी।

जहरीली शराब मामला : दिग्विजय और राजपूत आमने-सामने

भोपाल, देशबन्धु। सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मंत्री गोविंद राजपूत आमने-सामने आ गए हैं। दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि जानलेवा शराब बनाने और बेचने वालों को भाजपा नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण था। उन्होंने यह भी कहा कि जहरीली शराब मामले में उनके परिजन भी शामिल हैं।

इससे नाराज मंत्री राजपूत ने वीडियो जारी कर कहा कि विपक्ष राजनीति करने के बजाय सच्चाई सामने लाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के किसी व्यक्ति या परिवार को बदनाम करने वाली भ्रामक जानकारी प्रसारित न की जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि किसी गांव के एक व्यक्ति का संबंध मेरे परिवार से है अथवा वह मेरा रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं पुलिस अधीक्षक सागर से स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री राजपूत द्वारा मंगलवार रात जारी इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने उनके द्वारा दी गई कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद एक बैनर के आधार पर मंत्री राजपूत को घेरा और एक शराब ठेकेदार का नाम उनसे जोड़ दिया।

अधिकारियों को त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

भोपाल, देशबन्धु। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना। सिंह ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जनसमस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जिन प्रकरणों में विभाग की कार्रवाई आवश्यक है, उन्हें शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री राजेन्द्र सिंह राजपूत उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक जनसमस्या का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर उसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश सरकार जनहित से जुड़े विषयों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आमजन की जनसमस्याओं का समाधान और उन्हें शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करना, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, 8 अक्टूबर तक चलेगा अभियान, कहा-

आंगनबाड़ी को समाज से जोड़कर पोषण अभियान को जनआंदोलन बनाएं

बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के में सहयोग के लिए एम्स सहित 4 संस्थाओं से एमओयू

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का बुधवार को इंदौर से राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। 'हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' थीम के साथ 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य को लेकर जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वस्थ बच्चे ही प्रदेश और देश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव हैं। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को अभिभावकों, सरपंचों, पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों तथा सामाजिक और

सांस्कृतिक संस्थाओं से जोड़ा जाए। समाज की सक्रिय भागीदारी से आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए प्रयोग करने तथा सफल नवाचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करने का भी आह्वान किया, जिससे दूसरे केंद्र भी उनसे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा कि पोषण माह के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा। गर्भवती और धात्री माताओं को पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और बच्चों की देखभाल के प्रति जागरूक करने के साथ कुपोषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान रहेगा। मंत्री ने बताया कि विभाग ने आंगनबाड़ी भवनों की उपलब्धता बढ़ाने, मिनी आंगनबाड़ियों को मुख्य आंगनबाड़ी में उन्नयन करने और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के प्रयास किए हैं।

स्थानीय अनाज और पारंपरिक व्यंजनों पर जोर

पोषण माह के शुभारंभ पर लता मंगेशकर सभागृह परिसर में पोषण मेला और रेसिपी प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। यहां टेक होम राशन, गर्म पका भोजन, स्थानीय दालों, चना, मूंगफली, सोया, दूध एवं दुग्ध उत्पादों, मिलेट्स और मौसमी सब्जियों से तैयार पौष्टिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। 'नो योर प्रोटीन-अपने प्रोटीन को पहचानें' अभियान के जरिए परिवारों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रोटीन के स्रोतों और संतुलित आहार के महत्व की जानकारी दी गई।

पोषण माह के शुभारंभ अवसर पर बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए चार संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन भी किए गए। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, एम्स, आईपीई ग्लोबल और नई दिशा फाउंडेशन के साथ हुए एमओयू के माध्यम से बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

राज्यसभा सांसद डॉ. कविता पाटीदार ने कहा कि 'हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' के संदेश के साथ बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने पोषण ट्रैकर, वन स्टॉप सेंटर और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

मप्र में साढ़े 7 हजार पुलिस की भर्ती होगी

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर से शुरू होंगे और अभ्यर्थी 6 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन की सुविधा 11 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। संभावित लिखित परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी। आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को प्रदेश के 55 जिलों में से अपनी पसंद की इकाई का चयन करना होगा। जिस इकाई में नियुक्ति मिलेगी, वहां कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही दूसरी इकाई में स्थानांतरण किया जा सकेगा। कुल 7,500 पदों में विशेष सशस्त्र बल के 700 और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर आरक्षक के 6,800 पद शामिल हैं। आवेदन के समय अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह किस संवर्ग के आरक्षक पद के लिए आवेदन कर रहा है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासकीय रेल पुलिस की भोपाल, इंदौर और जबलपुर इकाइयों में भी की जाएगी।परीक्षा केंद्र पर आधार आधारित जैवमितीय सत्यापन होगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।

शारीरिक मापदंड: विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर आरक्षक के अन्य संवर्गों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर निर्धारित है।

निवाड़ी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा–

खेती को जीविकोपार्जन नहीं, लाभ का व्यवसाय बनाएं

किसानों की आय बढ़ाने उन्नत तकनीक और गुणवत्तापूर्ण बीज पर जोर

भोपाल/निवाड़ी, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक कृषि यंत्र और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाई जाए। कृषि को केवल जीविकोपार्जन का साधन न मानकर किसानों के लिए लाभ का व्यवसाय बनाया जाना चाहिए। आने वाले समय में कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ और सबकी समृद्धि की सबसे बड़ी गारंटी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को निवाड़ी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार किसानों के हित में पूरे वर्ष निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। डॉ. यादव ने किसानों से दुग्ध उत्पादन, श्रीअन्न, मत्स्य पालन और उद्यानिकी सहित अपनी रुचि के क्षेत्रों में नई शुरुआत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार खेत से लेकर फैक्ट्री तक किसानों के साथ खड़ी है। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, वैज्ञानिक पद्धतियों और कृषि यंत्रों के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों को कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से सीधे संवाद का अवसर दे रहा है। प्राकृतिक और जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिंचाई, बिजली और कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने पर सरकार लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जा रही है। खरीफ और रबी फसलों के ऋण की चुकौती अवधि छह-छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है। प्रदेश में ढाई करोड़ किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया गया है।

प्रगतिशील किसान और मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

कार्यक्रम में संरक्षित खेती, औषधीय खेती, निजी कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्र अनुदान, डेयरी प्लस, गौ-मैत्री योजना, प्राकृतिक खेती और मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। कक्षा दसवीं की प्रवीण सूची में प्रदेश में नौवां स्थान प्राप्त करने वाली निवाड़ी की छात्रा शिवानी कुशवाहा सहित जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं का भी सम्मान किया गया।

मधुबन में शिकारी बेखौफ: नीलगाय का शिकार कर जंगल से हुए फरार

शहर से महज पांच किलोमीटर दूर खेत में मिले नीलगाय के अवशेषों से मचा हड़कंप, वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल–रात में गश्त कर रहा था कौन?

टीकमगढ़। शहर से महज पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित मधुबन के जंगलों में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। मोहनपुरा-सुधासागर रोड स्थित मधुबन सब रेंज के जंगल से लगे खेत में मंगलवार सुबह नीलगाय का सिर और शरीर के अवशेष मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया वन विभाग ने इसे शिकार का मामला माना है और देर रात घटना होने की आशंका जताई है। खेत मालिक मनोज यादव के भाई श्रीराम यादव सुबह खेत पहुंचे तो वहां नीलगाय के कटे हुए अवशेष देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल मामले की सूचना डिप्टी रेंजर नरेंद्र नायक को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर नीलगाय का सिर और शरीर के अन्य हिस्से अलग-अलग स्थानों पर पड़े मिले। अवशेषों की स्थिति ने सामान्य मौत की संभावना को खारिज करते हुए शिकार की आशंका को बल दिया। रेंजर सौरभ जैन ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। नीलगाय का अधूरा शव मिला है। शिकार किस हथियार या किस तरीके से किया गया, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर केपी पटेरिया द्वारा अवशेषों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और घटना से जुड़े अन्य तथ्य स्पष्ट होंगे। घटना ने वन विभाग की रात्रिकालीन गश्त और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के इतने करीब जंगल में कथित तौर पर शिकार की वारदात हो जाना और आरोपियों का मौके से निकल जाना विभागीय निगरानी के लिए चुनौती है।

16 को जिला मुख्यालय में गरजेंगे किसान, ट्रैक्टर-वाहन रैली से दिखाएंगे ताकत

टीकमगढ़, देशबन्धु। किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ इस बार जिला मुख्यालय पर अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। संगठन की ओर से 16 सितंबर को टीकमगढ़ में ट्रैक्टर एवं वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसके बाद जिला प्रशासन को तीन अलग-अलग ज्ञापन सौंपे जाएंगे। संगठन का दावा है कि जिले के इतिहास में पहली बार किसी किसान संगठन द्वारा इस तरह की ट्रैक्टर एवं वाहन रैली निकाली जा रही है।

भारतीय किसान संघ हर वर्ष सितंबर माह में राष्ट्रीय ज्ञापन दिवस मनाता है। इसी क्रम में जिले की सभी नौ तहसीलों में पहले ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। 10 सितंबर को मोहनगढ़, दिगौड़ा, बल्देवगढ़ और खरगापुर, जबकि 11 सितंबर को टीकमगढ़, लिधौरा, जतारा और पलेरा तहसील में ज्ञापन दिए जाएंगे। इसके बाद 14 सितंबर को बड़ागांव धसान तहसील में किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तहसील स्तर के कार्यक्रमों के बाद 16 सितंबर को जिला मुख्यालय पर बड़ा आयोजन होगा। भारतीय किसान संघ के अनुसार सभी किसान पुरानी टेहरी तालाब बायपास रोड स्थित जिला कार्यालय पर एकत्रित होंगे। यहां से ट्रैक्टर एवं वाहनों के साथ रैली निकाली जाएगी, जो हायर सेकेंडरी स्कूल, ताल दरवाजा, स्टेट बैंक और मिश्रा तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी।कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों की विभिन्न मांगों एवं जिला स्तरीय समस्याओं को लेकर तीन ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

इनमें एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम, दूसरा मुख्यमंत्री के नाम और तीसरा स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर के नाम होगा।भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष शिव मोहन गिरि ने जिले के किसानों से अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों की एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इस शक्ति को महाशक्ति बनाने के लिए प्रत्येक किसान की भागीदारी जरूरी है।

बंडा शराब कांड के बाद विधायक यादवेंद्र सिंह ने टीकमगढ़ में अवैध शराब पर सख्ती की मांग उठाई

टीकमगढ़, देशबन्धु। सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई जनहानि के बाद टीकमगढ़ में भी अवैध और मिलावटी शराब के कारोबार को लेकर चिंता बढ़ गई है। टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह ने जिले में अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और शराब की गुणवत्ता की सघन जांच कराने की मांग को प्राथमिकता से उठाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, ढाबों और अन्य संभावित अवैध ठिकानों पर कच्ची अथवा रासायनिक पदार्थों से तैयार शराब के निर्माण और बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। आवेदन में जिले की शासकीय मदिरा दुकानों के स्टॉक का सत्यापन कराने के साथ वहां उपलब्ध शराब की गुणवत्ता की सघन जांच कराने की मांग भी की गई है।

अवैध शराब पर शिकंजा, बमोरीकलां पुलिस ने जब्त की 65 लीटर शराब

टीकमगढ़।, देशबन्धु। सागर जिले में जहरीली शराब की घटना के बाद अवैध एवं जहरीली शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में बमोरीकलां थाना पुलिस ने 7 और 8 सितंबर को अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर 11 प्रकरण दर्ज किए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 39 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब और 142 क्वार्टर सफेद प्लेन मदिरा जब्त की, जिसकी कुल मात्रा 25.56 लीटर बताई गई है। पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन से जुड़े मामलों में आरोपितों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को शराब के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की पहल भी की। पुलिस टीम ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग, कलरा और कंजना पहुंची। यहां चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को कच्ची हाथ भट्टी शराब और जहरीली शराब के सेवन से होने वाले गंभीर शारीरिक नुकसान की जानकारी दी गई। सागर की घटना का हवाला देते हुए ग्रामीणों से अवैध शराब से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस तक पहुंचाने की अपील की गई।इसके बाद सरपंच और कोटवार के माध्यम से गांव की महिलाओं को पंचायत भवन में बुलाकर शराब के सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक किया गया। पुलिस ने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि गांव के वरिष्ठ नागरिकों, पंचायत प्रतिनिधियों और कोटवार के सहयोग से अवैध शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जाए।दिनऊ, खरगूपुरा, कंजना, कलरा और पहाड़ी बुजुर्ग सहित अन्य गांवों में जनजागरूकता रथ के माध्यम से भी ग्रामीणों को अवैध एवं जहरीली शराब के खिलाफ सचेत किया जा रहा है।

बालाघाट की घटना को लेकर आदिवासी कांग्रेस मुखर, मृत बच्चों के परिजनों को एक-एक करोड़ मुआवजे की मांग

बल्देवगढ़, देशबन्धु। बालाघाट जिले में आदिवासी बैगा समाज के मासूम बच्चों की दुखद मौत की घटना को लेकर आदिवासी कांग्रेस कमेटी ने गहरी चिंता और आक्रोश जताया है। संगठन ने घटना की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम बल्देवगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि घटना ने पूरे आदिवासी समाज को गहरे सदमे और पीड़ा में डाल दिया है। संगठन ने मांग की कि मृत प्रत्येक बच्चे के परिजन को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता एवं मुआवजा दिया जाए। साथ ही घटना की निष्पक्ष जांच कर स्वास्थ्य विभाग अथवा किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आदिवासी कांग्रेस ने प्रभावित परिवारों के बच्चों की शिक्षा और परिवार के भरण-पोषण की उचित व्यवस्था सरकार से कराने की मांग भी रखी। इसके अलावा आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को तत्काल मजबूत करने तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया।

बिजली के ट्रांसफार्मर पर बैठा राष्ट्रीय पक्षी मोर, करंट लगने से मौत

बल्देवगढ़, देशबन्धु। क्षेत्र के ग्राम सुहागी में बिजली के ट्रांसफार्मर पर बैठे राष्ट्रीय पक्षी मोर की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और मृत मोर को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए बल्देवगढ़ पशु अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि ग्राम पंचायत भेलसी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुहागी में मोर बिजली के ट्रांसफार्मर पर बैठा था। इसी दौरान वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की नजर जब मृत मोर पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल वन विभाग को सूचना दी।सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ग्राम सुहागी पहुंची। मौके पर निरीक्षण के दौरान मृत पक्षी की पहचान राष्ट्रीय पक्षी मोर के रूप में की गई। वन विभाग के अमले ने मोर को कब्जे में लेकर पशु अस्पताल बल्देवगढ़ पहुंचाया, जहां चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया। पशु अस्पताल के चिकित्सक के अनुसार परीक्षण के दौरान मोर के पंख जले हुए मिले तथा सीने पर भी जलने के निशान पाए गए। प्रारंभिक जांच में बिजली का करंट लगने से मोर की मौत होना सामने आया है। बिजली के फॉल्ट के कारण हादसा होने की बात भी सामने आई है।वन विभाग के डिप्टी रेंजर खान ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। मृत पक्षी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बल्देवगढ़ पशु अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभागीय अधिकारियों के समक्ष नियमानुसार राष्ट्रीय पक्षी का दाह संस्कार किया जाएगा।

डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने के विरोध में 14 से धरना

टीकमगढ़, देशबन्धु। मवई ग्राम में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में कार्रवाई की मांग अब आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 14 सितंबर से संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन के सामने अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन करने की सूचना देते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन सौंपा है। मोर्चा की ओर से दिए गए आवेदन में बताया गया कि 30 अगस्त 2026 को मवई ग्राम में स्थापित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। घटना के संबंध में सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा देहात थाना टीकमगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।आवेदन में आरोप लगाया गया है कि घटना के दस दिन बीत जाने के बाद भी 9 सितंबर तक प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे डॉ. आंबेडकर के अनुयायियों और बहुजन समाज में रोष व्याप्त है।संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई नहीं होने के विरोध में 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। प्रस्तावित धरना संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन के सामने आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मोर्चा ने प्रशासन से अनुमति प्रदान करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

बिजली चोरी के मामलों में राहत का मौका, 12 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

प्री-लिटिगेशन मामलों में सिविल दायित्व पर 30 प्रतिशत तक और लिटिगेशन मामलों में 20 प्रतिशत तक छूट, ब्याज में 100 प्रतिशत राहत

टीकमगढ़, देशबन्धु। बिजली चोरी से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण के लिए 12 सितंबर 2026, शनिवार को जिला न्यायालय टीकमगढ़ परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज पात्र प्रकरणों में संबंधित उपभोक्ताओं को विशेष छूट का लाभ मिलेगा। शहर वितरण केंद्र, टीकमगढ़ ने पात्र उपभोक्ताओं से लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर अधिकतम 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही निर्धारित अवधि में भुगतान करने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। इसी तरह लिटिगेशन प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत तक की छूट और ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाएगा। हालांकि यह राहत निर्धारित पात्रता, नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी तथा छूट का लाभ एकमुश्त भुगतान करने पर ही मिलेगा। विद्युत विभाग के अनुसार बिजली चोरी से संबंधित पात्र प्रकरणों में जिन उपभोक्ताओं को अपने मामले की स्थिति, पात्रता अथवा देय राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वे शहर वितरण केंद्र, टीकमगढ़ से संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही छूट का लाभ उठाएं और अपने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निराकरण कराएं।

80 हजार के लिए, शादी की तस्वीरें-वीडियो नहीं दिए

उपभोक्ता आयोग ने 70 हजार लौटाने के दिए आदेश

टीकमगढ़, देशबन्धु। विवाह समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के नाम पर पूरी राशि लेने के बाद भी तय सामग्री उपलब्ध नहीं कराना फोटोग्राफर के लिए महंगा साबित हुआ। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, टीकमगढ़ ने मामले में सेवा में कमी मानते हुए अनावेदक को 45 दिवस के भीतर विवाह समारोह की समस्त सामग्री उपलब्ध कराने अथवा 70 हजार रुपये वापस करने का आदेश दिया है।

आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा एवं सदस्य डॉ. प्रीति सिंह परमार ने मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता रत्नेश नायक ने परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी के अनुसार विवाह समारोह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डीवीडी एवं एल्बम तैयार कराने के लिए अनावेदक को कुल 80 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। इसके बावजूद तय समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। बार-बार आश्वासन के बाद भी जब विवाह समारोह की फोटो, वीडियो और एल्बम नहीं मिले तो परिवादी ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

मामले की सुनवाई में अनावेदक आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। परिणामस्वरूप प्रकरण का एकपक्षीय निराकरण किया गया। आयोग ने माना कि विवाह समारोह की फोटो एवं वीडियो महत्वपूर्ण जीवन-स्मृतियों से जुड़ी सामग्री है। भुगतान प्राप्त करने के बाद अनुबंध के अनुरूप सेवा उपलब्ध नहीं कराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवा में कमी है। आयोग ने आदेश दिया कि 45 दिवस के भीतर विवाह समारोह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डीवीडी, एल्बम और उपलब्ध डिजिटल सामग्री परिवादी को दी जाए। सामग्री उपलब्ध नहीं कराने पर 70 हजार रुपये वापस करने होंगे। इसके साथ ही मानसिक पीड़ा एवं असुविधा के लिए 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय के लिए 2 हजार रुपये भी देने होंगे। आदेश का पालन नहीं होने पर देय राशि पर वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी लागू होगा।

ग्राम स्वराज के अधिकारों को लेकर प्रदेशभर में निकलेगी सरपंच यात्रा

राष्ट्रीय सरपंच संघ ने कसी कमर, 12 सितंबर को टीकमगढ़ में होगा पड़ाव

टीकमगढ़, देशबन्धु। ग्राम पंचायतों के अधिकारों और ग्राम स्वराज की अवधारणा को लेकर राष्ट्रीय सरपंच संघ द्वारा मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज अधिकार बचाव यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर 9 सितंबर को होटल चपाती में राष्ट्रीय सरपंच संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलेभर के सरपंच एवं संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए।

राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर के नेतृत्व में प्रस्तावित यह यात्रा 11 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे मध्यप्रदेश में निकाली जाएगी। यात्रा का शुभारंभ 11 सितंबर को दतिया से होगा, जबकि 30 सितंबर को भोपाल में इसका समापन किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि यात्रा 11 सितंबर की रात टीकमगढ़ पहुंचेगी। इसके अगले दिन 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे होटल चपाती, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास अनंतपुरा में यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे यात्रा छतरपुर के लिए रवाना होगी।

राष्ट्रीय सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के अधिकारों, ग्राम स्वराज और पंचायत व्यवस्था से जुड़े विषयों को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के बीच जागरूकता पैदा करना है। बैठक में यात्रा के सफल आयोजन और जिले में सरपंचों की सहभागिता को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमर सिंह, प्रदेश महामंत्री प्रमोद मिश्रा, टीकमगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष सरदार सिंह यादव, बल्देवगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष सोनू महाराज, पलेरा ब्लॉक अध्यक्ष महेश यादव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सरपंच उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह बुंदेला ने जिले के सभी सरपंचों से 12 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करने की अपील की है।

सार-समाचार

शिक्षक बलीराम अहिरवार राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित

दमोह, देशबन्धु। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने नवाचार के मॉडल बनाकर छात्र छात्राओं को पढ़ाना प्रयोग के माध्यम से समझाना गृह संपर्क से बच्चों को नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना और विभिन्न प्रकार की कला क्षेत्र की गतिविधियों में निपुण करने के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय आगमन पर बलिराम अहिरवार के द्वारा बताया गया कि अत्यंत ही गौरवशाली क्षण और हर्ष का विषय है यह केवल मेरा पुरस्कार नहीं अपितु समस्त विद्यालय परिवार के लिए पुरस्कार है विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया।

दमोह नगर मंडल भाजपा की कार्यसमिति बैठक संपन्न

दमोह, देशबन्धु। भारतीय जनता पार्टी दमयंती नगर मंडल की कार्यसमिति बैठक 'संकल्प सेवा अभियान' को लेकर संपन्न हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों एवं संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सामाजिक जीवन के उपलक्ष्य में सेवा भाव के साथ किया जा रहा है। बैठक में मंडल प्रभारी श्रीमती सुमन उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष रमाकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद विजय जैन सहित दमयंती नगर मंडल के समस्त पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी एवं संयोजक तथा बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यसमिति बैठक में अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता के साथ सेवा, संकल्प एवं समर्पण की भावना से अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया।

थाना नोहटा पुलिस द्वारा अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई

दमोह, देशबन्धु। पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में थाना नोहटा पुलिस द्वारा एसडीओपी तेन्दूखेड़ा के मार्गदर्शन में विगत 02 दिवस में बड़ी कार्यवाही की गई है। नोहटा पुलिस द्वारा अवैध शराब मिलने पर 16 प्रकरण दर्ज किये गये है व आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।6 सितम्बर 26 को कुल 13 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें लगभग 65 लीटर शराब जप्त की गई व लगभग 20 क्विंटल लोहान नष्ट किया गया । 08 सितमबर 26 को कुल 02 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें लगभग 15 लीटर शराब जप्त की गई व लगभग 15 क्विंटल लोहान नष्ट किया गया । उक्त कार्यवाही में तहसीलदार जबेरा आशुतोष गुप्ता उनि अभिषेक पटैल थाना प्रभारी नोहटा, सउनि नागेन्द्र सिंह, सउनि अकरम खान, प्रआर जितेन्द्र, प्रआर प्रदीप, प्रआर कामता, प्रआर दीपक, प्रआर प्रवीण, प्रआर प्रदीप, प्रआर नन्नेभाई, प्रआर मुकेश, आर. सोहिल, आर. सुनील, आर. देशराज, आर. देवराज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

लायसेंसी दुकानों से गांव-गांव अवैध शराब सप्लाई रोकने सौंपा ज्ञापन

दमोह/तेन्दूखेड़ा, देशबन्धु। भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशामुक्ति अभियान के माध्यम से क्षेत्र में हजारों जगह अवैध शराब पकड़ाई गई है । तत्कालीन समय में जहरीली शराब से सागर के बंडा क्षेत्र में हुई मौतों जैसा हाल तेंदूखेड़ा क्षेत्र में घटित न हो जिसके लिए भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा एक ज्ञापन सौपा गया। जिसमें बताया कि तेंदूखेड़ा विकासखण्ड अंतर्गत आने वाली शराब दुकान तेंदूखेड़ा, तारादेही, झलौन, तेजगढ़ से निरन्तर शराब ठेकेदारों गाँव गाँव में पहुँचाई जा रही है। शराब दुकान के सीसीटीवी फुटेज जाँच कर उक्त शराब दुकान पर कार्यवाही की किया जाने एवं लायसेंस रद्द करने, प्रत्येक शराब दुकान की सैंपलिंग कर जाँच कराई जाने, जिस थाना प्रभारी द्वारा अवैध शराब बेचने वाले पर कार्यवाही न किये जाने पर उस थाना प्रभारी को थाने से हटाये जाने की मांग की गई। उक्त बिन्दुओं पर अतिशीघ्र दण्डात्मक कार्यवाही कर अवगत कराया जावे अन्यथा कि स्थिति में भगवती मानव कल्याण संगठन समस्त क्षेत्रवासियों सहित विशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा जिसकी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।

जबेरा में बिक रही अवैध शराब के विरोध में संगठन ने ज्ञापन सौंपा

दमोह, देशबन्धु। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने जबेरा तहसील पहुंचकर एसडीएम के नाम एवं थाना प्रभारी जबेरा को ज्ञापन सोंपा। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह राजपूत एवं संभागीय अध्यक्ष डॉ सुजान सिंह ने बताया कि संगठन द्वारा अभी तक दर्जनों ज्ञापन गांव गांव अबैध शराब विक्रय के खिलाफदिए गए हैं लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है हम सभी ने देखा कि सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 35 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है और 150 लोगों से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसी घटना हमारे जबेरा विधानसभा में ना घटे इसी उद्देश्य को लेकर संगठन ने ज्ञापन सौंपा ।संगठन के लोगों ने कहा अगर जबेरा में कच्च शराब या शासकीय शराब दुकानों की शराब पिने से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है या मृत्यु होती है तो उसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी साथ ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश सचिव बिनोद सिंह ने कहा कि आगे से पुलिस द्वारा अबैध शराब विक्रय बालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो संगठन द्वारा प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मगन यादव, जिला सचिव सुरेश राय, पार्टी के जिला सचिव पर्वत सिंह, संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश अहिरवार, ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश सिंह, पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष भुजबल सिंह, संगठन एवं पार्टी के समस्त जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह का आग़ाज़, रैली निकालकर ली गई पोषण की शपथ

दमोह, देशबन्धु। महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रतिवर्ष चलाई जाने वाले पोषण माह अभियान का आगाज हो गया। हटा और बटियागढ़ ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रो में रैली निकाल कर पोषण की शपथ और संकल्प दिलाया गया ताकि लोग पोषण और स्वास्थ्य से सम्बंधित लाभ और जानकारियां ले सकें साथ ही शासन की योजनाओं से भी रूबरू हो

परियोजना अधिकारी शिवराय ने बताया कि 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, आज पहले दिन रैली निकाल कर पोषण शपथ दिलाकर सभी को संकल्प दिलाया गया। ग्रामीण अंचलों में बच्चों महिलाओ, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं माताओ और किशोरी बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर रखने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलाया जाता है, कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के मार्गदर्शन में हमारा प्रयास है कि सरकारी कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाया जाए, समुदायों से जोड़ा जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इस कार्यक्रम का महत्व समझ में आए।

ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में पर्याप्त पोषण का अभाव होता है, जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं हो पता, बच्चों में शारीरिक कमजोरी रोकने के लिए भी यह अभियान कारगर सिद्ध होता है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में वजन कम होने की बात सामने आ रही है वहीं शहरी क्षेत्र में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एवं जंक फूड के कारण ओवरवेट की बात आ रही है जो भी एक कमी है। पोषण माह के दौरान आवश्यक सभी जानकारियां, पोषण प्रदर्शनी, स्वास्थ्य परीक्षण, खान पान आदि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगो तक पहुचेगे।

दस्तक अभियान के तहत विद्यार्थियों को स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण का संदेश

दमोह, देशबन्धु। दस्तक अभियान के अंतर्गत हाथ धोने के महत्व, स्वच्छता एवं पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से टीएएफटीम द्वारा स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से दमोह जिले के विभिन्न ब्लॉकों के माध्यमिक विद्यालयों में जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई।

गतिविधि के दौरान चित्र कार्ड के माध्यम से कहानी एवं संवादात्मक प्रस्तुतीकरण के द्वारा विद्यार्थियों को प्रमुख स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी संदेश प्रभावी रूप से प्रदान किए गए। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता द्वारा र्व घोल तैयार करने की विधि तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हाथ धोने की सही एवं निर्धारित प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। पथरिया ब्लॉक में आयोजित गतिविधि में बीसीएम एवं सीएचओ तथा अन्य ब्लॉकों में टीम की सहभागिता रही, जिससे गतिविधि को अधिक प्रभावी एवं सहभागितापूर्ण बनाने में सहयोग प्राप्त हुआ। विभिन्न विभागों एवं हितधारकों के समन्वित प्रयास एवं सक्रिय सहभागिता के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वच्छता, हाथ धोने तथा स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण संदेशों के प्रति प्रभावी जागरूकता सुनिश्चित की गई।

हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' थीम पर वार्ड क्रमांक 9 केंद्र क्रमांक 20 में मनाया राष्ट्रीय पोषण माह

पन्ना, देशबन्धु। राष्ट्रीय पोषण माह-2026 के तहत बुधवार को आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड क्रमांक 9 में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' की थीम के तहत बच्चों, महिलाओं और अभिभावकों को पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान संतुलित आहार, पर्याप्त प्रोटीन, बच्चों के प्रारंभिक विकास तथा मातृ स्वास्थ्य के महत्व की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध पोषण आहार एवं स्थानीय खाद्य सामग्री के उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक एवं संतुलित आहार बेहद जरूरी है। साथ ही अभिभावकों से आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की गई।

कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि आंगनवाड़ी केवल बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने का केंद्र नहीं, बल्कि पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल और प्रारंभिक बाल विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है।

कार्यक्रम में सुपरवाइजर अंजली गुप्ता, अमित नायक एवं आकाश शर्मा। कार्यकर्ता कमलेश शर्मा सहायिका गिरजा नामदेव सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सांप को भगाने जलाई मिर्ची से पटाखों में लगी आग, पटाखे फूटने से युवक झुलसा

दमोह, देशबन्धु। देहात थाना क्षेत्र की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत किल्लाई गांव में मंगलवार शाम पांच बजे एक घर में रखे पटाखों में आग लगने से हुए विस्फोट के कारण एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी लगते ही देहात थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचे और घायल के बयान दर्ज करने के बाद मामले में जांच शुरू की गई। देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय व चौकी प्रभारी प्रियंका पटेल ने बताया कि नेघायल की पहचान 30 वर्षीय निहाल पिता राजकुमार कुंचबदिया निवासी किल्लाई गांव के रूप में हुई है।

घायल ने बताया कि घर में पटाखे रखे थे। शाम के समय एक सांप घर में घुस गया जिसे भगाने के लिए आग जलाई और मिर्च पाउडर जलाया था। इसी दौरान पटाखों में आग लग गई और विस्फोट हो गया।वह पटाखों के नजदीक ही खड़ा था जिसमें विस्फोट के कारण वह झुलस गया। परिजन गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। घायल के बयान दर्ज किए गए और मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

नवनिर्मित आयुष विभाग के भवन में टपक रहा पानी निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

पन्ना, देशबन्धु। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा जिला आयुष विभाग के लिए बनाई गई नवनिर्मित बिल्डिंग में जगह-जगह सीलन और पानी टपकने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि इस भवन का हैंडओवर कुछ समय पूर्व ही हुआ है, इसके बावजूद भवन की दीवारों और अन्य हिस्सों में अत्यधिक सीलन दिखाई दे रही है। ऐसे में नवनिर्मित भवन की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

जानकारी के मुताबिक बारिश के दौरान बिल्डिंग के कई कमरों में पानी टपकने लगा। लगातार पानी टपकने के कारण कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सामान को सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ा। वहीं भवन की दीवारों पर भी नमी और सीलन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

भवन की सीढ़ियों पर भी अत्यधिक सीलन देखी जा रही है। इतना ही नहीं, सीढ़ियों के नीचे रखे दवाइयों के कार्टून के आसपास भी सीलन पहुंच रही है। यदि समय रहते इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया तो दवाइयों और अन्य सामग्री के खराब होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भवन का निर्माण हाल ही में हुआ और इसे विभाग को हैंडओवर भी कर दिया गया, तो इतनी जल्दी भवन में पानी रिसने और सीलन की समस्या कैसे सामने आ गई? क्या निर्माण के दौरान गुणवत्ता के मानकों का पालन किया गया था? क्या भवन के निर्माण कार्य की तकनीकी जांच हुई थी?

मामले की जानकारी जिला प्रशासन के संज्ञान में भी आई है। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित निर्माण एजेंसी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और भवन की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

कॉम्बिंग गश्त में 25 गिरफ्तारी वारंट तामील, 23 वारंटी न्यायालय में पेश

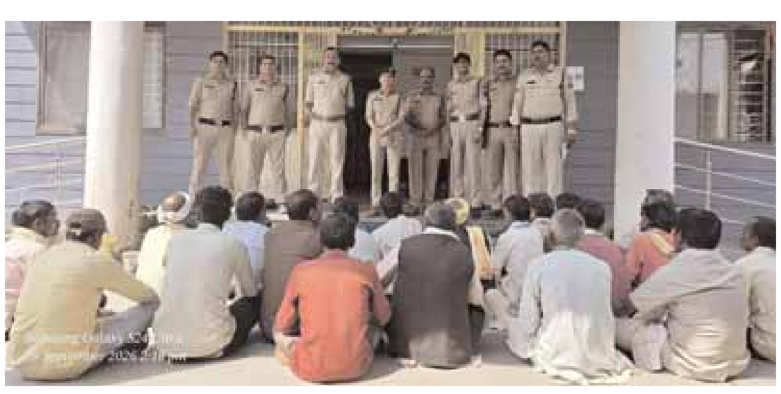

दमोह/तेंदूखेड़ा, देशबन्धु। तेंदूखेड़ा पुलिस द्वारा चलाए गए कॉम्बिंग गश्त के दौरान विभिन्न मामलों में लंबित गिरफ्तारी वारंटों की तामीली के साथ शराब संबंधी तीन कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 25 गिरफ्तारी वारंट तामील किए। पुलिस जांच में 25 वारंटों में से 2 वारंटी मृत पाए गए, जबकि 1 वारंट कैंसलेशन का निकला।

इसके बाद शेष वारंटों में कार्रवाई करते हुए 23 वारंटियों को बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसी अभियान के दौरान पुलिस द्वारा एक स्थाई वारंटी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान नगर निरीक्षक सरोज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में तेंदूखेड़ा थाना पुलिस का समस्त स्टाफसक्रिय रहा। पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर वारंटियों की तलाश की और लंबित न्यायालयीन वारंटों की तामीली की।

पुलिस द्वारा अभियान के दौरान अवैध शराब के संबंध में भी तीन कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा फरार एवं वारंटियों की धरपकड़ के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही अवैध शराब सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञान की आंख खुलते ही टूटती है मोह की नींद, सम्यक पुरुषार्थ से सच होता है जीवन का सपना- निर्यापक मुनि समतासागर

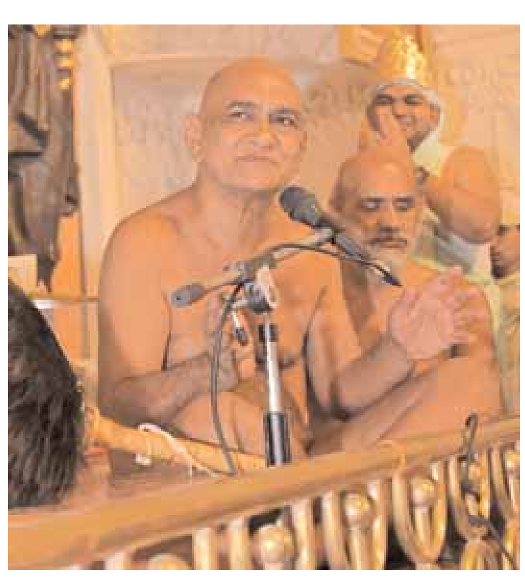

दमोह/हटा, देशबन्धु। *निर्यापक श्रमण मुनि समतासागर महाराज ने ेंज े स्पमि श्रृंखला के अंतर्गत 'स्पमि पे ं क्तमंउ' विषय पर जीवन के सपने, मोह की निद्रा, जाग्रति, अनुप्रेक्षा और सम्यक पुरुषार्थ का गहन विवेचन किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता अविनाश जैन 'विद्यावाणी' एवं क्षेत्रीय प्रचारमंत्री जय कुमार जलज ने बताया कि मुनि श्री का यह संदेश युवाओं को आधुनिक लक्ष्य-निर्धारण के साथ जैन दर्शन के जीवनोपयोगी सूत्रों को जोड़ने की प्रेरणा देता है। मैं कौन हूं कर्मों का हिसाब, अनुप्रेक्षा और हल' जैसे सूत्र जीवन के लक्ष्य को केवल उपलब्धि ही नहीं, बल्कि आत्म-विकास और सार्थकता के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को समझने का अर्थ संसार को झूठा मानना नहीं, बल्कि उसकी अनित्यता को पहचानना है। संसार का अपना अस्तित्व है, लेकिन सांसारिक सुख, संबंध, शरीर, धन, पद और परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। मुनि ने कहा कि जीवन की वास्तविकता को एक पंक्ति में समझना हो तो कहा जा सकता है, आंख खुली,सपना गया;आंख लगी,अपना गया। दो दिन का मेहमान तू, श्वास रुकी, जपना गया। रात में देखा गया सपना आंख खुलते ही समाप्त हो जाता है,उसी प्रकार मोह और अज्ञान की नींद में मनुष्य चलते-फिरते हुए भी अनेक सपने देखता रहता है। जब ज्ञान की आंख खुलती है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है।उन्होंने जैन दर्शन में अनित्यता के चिंतन को समझाते हुए कहा कि सूर्य-चंद्रमा का उदय-अस्त, ऋतुओं का परिवर्तन, बहती नदी, घटती श्वास, ढलता यौवन और धूप में पिघलती ओस की बूंदकृये सभी जीवन की क्षणभंगुरता का संदेश देते हैं। संसार मायाजाल नहीं है, बल्किसंसार के भीतर मौजूद वैभव और परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। इन्हें स्थायी मानकर उनसे आसक्ति करना ही मोह का कारण बनता है। मुनि ने कहा कि मनुष्य मोहिनी कर्म के प्रभाव में सत्य और असत्य का विवेक खो देता है। वह शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और घर, धन, वाहन, नौकरी, व्यवसाय तथा परिवार को अपना मानकर उनके प्रति आसक्ति बढ़ाता रहता है। कल्पनाएं कितनी भी सुंदर क्यों न हों, वे व्यक्ति को सुला सकती हैं, जगा नहीं सकतीं।*

मुनि श्री ने कहा कि बंद आंखों के सपने हमेशा सच नहीं होते, लेकिन जाग्रत अवस्था में देखे गए लक्ष्य और उन्हें साकार करने का पुरुषार्थ जीवन को नई दिशा देता है। उन्होंने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के उस संकल्प का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कुण्डलपुर के बड़े बाबा को छोटे मंदिर से निकालकर भव्य मंदिर में बड़े सिंहासन पर विराजमान करने का सपना खुली आंखों से देखा और उसे साकार करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ किया। आज उस संकल्प की परिणति समाज के सामने है।उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन उस लक्ष्य को सम्यक पुरुषार्थ, अनुप्रेक्षा, अपरिग्रह और आत्मबोध से जोड़ें। उन्होंने कहा कि सपने केवल देखने के लिए नहीं, जागकर जीने और पुरुषार्थ से साकार करने के लिए होते हैं। मोह की नींद में देखे गए सपनों से जागिए, सत्य को पहचानिए और अपने श्रेष्ठ सपनों को 'डांम पज जतनम' के संकल्प के साथ साकार कीजिए।

पीड़ितों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, बंधाया ढांढस

इलाज में नहीं आने देंगे कोई कमी, बीएमसी में 24 घंटे निगरानी और बेहतर उपचार के निर्देश

सागर, देशबन्धु। बंडा के अवैध जहरीली शराब मामले से प्रभावित लोगों के उपचार और उनके परिजनों को संबल देने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने बीएमसी के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर भर्ती मरीजों का कुशलक्षेम जाना और उनके परिजनों से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने वार्ड में प्रत्येक मरीज के पास पहुंचकर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से बातचीत करते हुये पूछा कि परिवार में कौन-कौन है और उनकी क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री के संवेदनापूर्ण व्यवहार और भरोसा दिलाने वाले शब्दों से पीड़ित परिवारों को भावनात्मक संबल मिला। बीएमसी के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभारी डीन, अधीक्षक एवं वरिष्ठ चिकित्सकों से मरीजों के उपचार की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि सभी पीड़ितों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये और इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने आवश्यक दवाओं, जांचों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता चौबीसों घंटे सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों की निरंतर निगरानी रखने तथा उनकी स्वास्थ्य स्थिति में होने वाले प्रत्येक बदलाव पर तत्काल आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के उपचार के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। इस दौरान दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक गोपाल भार्गव, विधायक भूपेन्द्र सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन, विधायक प्रदीप लारिया, विधायक वीरेन्द्र सिंह लोधी, विधायक निर्मला सप्रे, विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी, महापौर संगीता तिवारी, निगमाध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार, रानी कुशवाहा एवं शैलेष केशरवानी, कमिश्नर दिलीप कुमार, डीआईजी एसएस चौहान, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया सहित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहा।

गणेशोत्सव व पर्युषण पर्व से पहले सफाई, बिजली और सड़क कार्यों की मांग को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन

सागर, देशबन्धु। आगामी गणेशोत्सव एवं पर्युषण पर्व को देखते हुये शनिचरी-लाजपतपुरा वार्ड के युवाओं ने विधायक शैलेंद्र जैन को ज्ञापन सौंपकर वार्ड में विशेष साफ सफाई, पर्याप्त विद्युत व्यवस्था एवं शेष सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की। युवाओं ने बताया कि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं और नागरिकों की आवाजाही बढ़ेगी, ऐसे में स्वच्छता, प्रकाश एवं सुगम आवागमन की बेहतर व्यवस्था आवश्यक है। विधायक जैन ने मांगों को गंभीरता से लेते हुये संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पर्व-त्योहार सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को त्योहारों से पहले सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा शेष सड़क कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिये। युवाओं ने त्वरित कार्यवाही के लिये विधायक का आभार व्यक्त किया।

नवागत संभागायुक्त दिलीप कुमार ने संभाला पदभार

सागर, देशबन्धु। नवागत संभागायुक्त दिलीप कुमार ने बुधवार को संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर सागर संभाग के संभागायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। पूर्व संभागायुक्त अनिल सुचारी ने उन्हें पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने से पूर्व श्री कुमार आयुक्त उद्योग, मप्र भोपाल तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम मप्र भोपाल अतिरिक्त प्रभार के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद संभागायुक्त दिलीप कुमार ने कार्यालय के अधिकारियों से भेंट की तथा संभाग में संचालित विभिन्न प्रशासनिक एवं विकास गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय कार्यों एवं प्राथमिकताओं के संबंध में चर्चा भी की।

भाजपा महिला मोर्चा मे अंकिता किंग को बनाया जिला नीति शोध प्रभारी

सागर, देशबन्धु। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मेघा दुबे के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी में संगठन द्वारा अंकिता किंग को भाजपा महिला मोर्चा में जिला नीति शोध प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। यह नियुक्ति संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, महिला प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी परांजपे, संभाग प्रभारी गौरव रणदेव, जिला प्रभारी लोकेंद्र पाराशर की सहमति तथा प्रदेश नेतृत्व की स्वीकृति से की गई है। अंकिता किंग की नियुक्ति की खबर मिलते ही भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में उत्साह का माहौल है। अंकिता किंग लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय एवं ऊर्जावान भूमिका निभाती रही हैं। उनकी सक्रियता, कार्य के प्रति समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा को देखते हुये उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। नवनियुक्त जिला नीति शोध प्रभारी अंकिता किंग ने संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व एवं जिलाध्यक्ष मेघा दुबे का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि वे पार्टी द्वारा दिये गये दायित्व का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगी, साथ ही महिला मोर्चा को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने तथा महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिये निरंतर प्रयास करेंगी। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अंकिता किंग को नई जिम्मेदारी के लिये शुभकामनायें देते हुये विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व और सक्रिय कार्यशैली से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।

जहरीली शराब कांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा पांच सूत्रीय ज्ञापन

सागर, देशबन्धु। बण्डा क्षेत्र में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों और अस्पतालों में उपचाररत लोगों के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सागर आगमन के दौरान मकरोनिया चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मकरोनिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में हुये प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाये। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी और मकरोनिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र कुर्मी मौजूद रहे। कांग्रेसजनों ने राज्यपाल के नाम संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में बण्डा जहरीली शराब कांड की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही तथा पीड़ित परिवारों को न्याय और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ सरकार की घोषित जीरो टॉलरेंस नीति का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन नही हुआ। पार्टी ने इस मामले में जिम्मेदारी तय करते हुये पूरे प्रकरण की स्वतंत्र न्यायिक एजेंसी से जांच कराने की मांग की। पूर्व मंत्री चौधरी ने कहा कि बण्डा जहरीली शराब कांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के बीच पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाने और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिये मुख्यमंत्री के पास दो मिनट का समय नही होना सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करता है। घटना की तह तक जाकर यह पता लगाया जाना जरूरी है कि जहरीली शराब का कारोबार किन परिस्थितियों में संचालित हो रहा था और इसके पीछे कौन लोग हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिये। देवेंद्र कुर्मी ने कहा कि बण्डा की घटना ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं। जहरीली शराब से लोगों की जान जाना सामान्य घटना नहीं है और इसके लिये जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। सरकार को पीड़ित परिवारों के साथ न्याय करना चाहिये तथा अवैध शराब के कारोबार को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। प्रदर्शन के दौरान विजय साहू, आरआर पारासर, संदीप चौधरी, पुरुषोत्तम शिल्पी, मनोज राय, अक्षय कुमार दुबे, सुरेंद्र सिंह चावड़ा, रोहित वर्मा, सीमा कमल चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नवागत कमिश्नर पहुंचे बीएमसी, भर्ती मरीजों का जाना हाल

सागर, देशबन्धु। बंडा में हुये अवैध जहरीली शराब हादसे के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुये नवागत संभागायुक्त दिलीप कुमार ने पदभार संभालते ही सीधे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचकर भर्ती पीड़ितों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थायें दुरुस्त रखने के निर्देश दिये। कमिश्नर दिलीप कुमार ने अस्पताल के वार्डों में जाकर भर्ती एक-एक मरीज की स्थिति देखी। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिजनों से सीधी बातचीत कर मिल रहे इलाज का फीडबैक लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन उनके बेहतर इलाज और सुरक्षा के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी प्रभावित मरीजों के बेहतर और त्वरित उपचार के लिये आवश्यक निर्देश दिये तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल, बीएमसी के प्रभारी डीन डॉ. अमर गंगवानी, अधीक्षक डॉ. राजेश जैन, डॉ. सौरभ जैन मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री सागर आये, औपचारिकता निभाकर चले गये, मृतक परिवारों की नहीं ली सुध: मोहासा

सागर, देशबन्धु। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सागर प्रवास को लेकर सवाल उठाते हुये इसे महज औपचारिकता बताया, आरोप लगाया कि बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई जनहानि के बावजूद मुख्यमंत्री मृतक परिवारों से मिलने बंडा नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस गंभीर घटना पर कांग्रेस पर आरोप लगाने के बजाय पिछले वर्षों में अवैध शराब के खिलाफ हुई कार्यवाही और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर जवाब देना चाहिये। मोहासा ने दावा किया कि सरकार द्वारा बताई जा रही मौतों की संख्या और जमीनी स्थिति में अंतर है। मौतों के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग करते हुये कहा कि सभी मृतकों के विसरा की जांच भोपाल की स्वतंत्र फॉरेंसिक लैब से कराई जानी चाहिये, ताकि जांच की निष्पक्षता को लेकर कोई सवाल न रहे। क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार और शराब की भट्टियों को लेकर ग्रामीणों की ओर से पहले भी प्रशासन को शिकायतें और ज्ञापन दिये गये थे। इसके बावजूद समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इसकी जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये। कार्यवाही केवल छोटे आरोपियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिये। पूरे अवैध शराब नेटवर्क की जांच के साथ कथित संरक्षण देने वालों और लापरवाही बरतने वाले पुलिस एवं आबकारी अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जानी चाहिए। मोहासा ने आबकारी विभाग की कथित क्लीनचिट पर भी सवाल उठाते हुये इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। क्लीनचिट किन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दी गई तथा इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार था, यह सार्वजनिक किया जाना चाहिये। उन्होंने घटना में दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की। मृतक परिवारों को दी जा रही 6 लाख रुपये की सहायता राशि को अपर्याप्त बताते हुये प्रत्येक मृतक परिवार को कम से कम 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। मृतकों के आश्रितों को भी उचित आर्थिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने की मांग रखी। मोहासा ने कहा कि कांग्रेस के अनुसार यह मामला केवल जहरीली शराब से हुई मौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे शासन प्रशासन की जवाबदेही भी जुड़ी है। मृतक परिवारों को न्याय मिलने तक कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी।

सीवरेज कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई जलापूर्ति पाइपलाइन, नपा ने तत्काल कराया मरम्मत कार्य

खुरई, देशबन्धु। नगरीय क्षेत्र की आवास कॉलोनी में बुधवार सुबह सीवरेज निर्माण कार्य के दौरान जलापूर्ति की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही नगर पालिका प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुये मौके पर टीम भेजकर मरम्मत कार्य शुरू कराया। सीएमओ राजेश मेहतेले के मार्गदर्शन में उपयंत्री शिवा मेहरा, जलापूर्ति व्यवस्था प्रभारी रामगोपाल अहिरवार एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक नीतेश श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों को बुलाकर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के दुरुस्तीकरण का कार्य प्राथमिकता से कराया गया। नगर पालिका की टीम के त्वरित प्रयासों से पाइपलाइन की मरम्मत कर जलापूर्ति व्यवस्था को पुनः सुचारू करने की कार्यवाही की गई। नपा अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परेशानी न हो, इसके लिये शिकायत या सूचना मिलते ही तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

काकागंज वार्ड में नवीन आंगनबाड़ी भवन का प्रस्ताव

सागर, देशबन्धु। काकागंज वार्ड में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों ने विधायक शैलेंद्र जैन से मुलाकात की। उन्होंने वार्ड में उपलब्ध रिक्त शासकीय भूमि की जानकारी देते हुये भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा। विधायक जैन ने संबंधित अधिकारियों को शासकीय भूमि पर आंगनबाड़ी भवन स्वीकृति का प्रस्ताव विभाग को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहां भी शासकीय भूमि उपलब्ध है, वहां बच्चों के लिये स्मार्ट एवं सुविधायुक्त आंगनबाड़ी भवन बनाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सागर विधानसभा क्षेत्र में किराये अथवा जर्जर भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता देते हुये 10 नये भवन स्वीकृत कराये गये हैं, साथ ही अन्य वार्डों से भी ऐसे केंद्रों के प्रस्ताव मांगे गये हैं, जहां भवन निर्माण के लिये शासकीय भूमि उपलब्ध है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण एवं सर्वांगीण विकास की आधारशिला हैं। स्मार्ट आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित वातावरण के साथ आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है।

ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर बांटी निःशुल्क दवायें

सागर, देशन्धु। आयुष्मान आरोग्य मंदिर भड़राना, बंडा द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्र. 36 ग्राम मंजला में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया तथा योगाभ्यास कराया गया। शिविर में वर्षा ऋतु में अपनाई जाने वाली ऋतुचर्या एवं दिनचर्या, स्वच्छता, संतुलित आहार और रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभ बताते हुये घर एवं आसपास पौधरोपण के लिये प्रेरित किया। इसके साथ ही सर्पदंश एवं आकाशीय बिजली से बचाव के आवश्यक उपायों की जानकारी, ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया।

बकाया राशि वसूलने में कोताही बर्दाश्त नहीं: मुख्य अभियंता

सागर, देशबन्धु। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सागर क्षेत्र के मुख्य अभियंता एसआर येमदे ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बकाया बिजली बिलों की वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वयं क्षेत्र का भ्रमण कर विच्छेदित कनेक्शनों का मौके पर निरीक्षण किया और बकायादार उपभोक्ताओं से चर्चा कर शीघ्र बिल जमा करने की समझाइश दी। रहली में अभियंताओं की बैठक के बाद मुख्य अभियंता ने गौरझामर वितरण केंद्र के अंतर्गत बैदवारा एवं पिपरिया ग्राम में विच्छेदित कनेक्शनों का निरीक्षण किया। बैदवारा में एक उपभोक्ता पर करीब 42 हजार रुपये की बकाया राशि पाये जाने पर परिजनों से चर्चा की, जिस पर शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया गया। मुख्य अभियंता ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी द्वारा राजस्व वसूली के लिये किये जा रहे प्रयासों की सराहना की जायेगी, वही लापरवाही मिलने पर कठोर कार्यवाही होगी। बैठक में राजस्व वसूली, नवीन एवं एचटी कनेक्शन, स्कूलों के लंबित कनेक्शन, सीएम हेल्पलाइन व 1912 शिकायतों के निराकरण तथा फेल ट्रांसफार्मरों को स्टोर में जमा कराने सहित निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिये।

अवैध शराब निर्माण के नेटवर्क का पर्दाफाश, 16 आरोपी दबोचे गए

नकली शराब बनाने की सामग्री और 250 लीटर से अधिक शराब जब्त, फरार आरोपियों पर इनाम घोषित

बण्डा, देशबन्धु। अवैध शराब के निर्माण और बिक्र के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुये थाना बण्डा एवं थाना विनायका में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध एवं अमानक शराब के साथ नकली शराब तैयार करने में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी बरामद की है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण और गांवों में इसकी सप्लाई के नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार 6 सितंबर को थाना बण्डा क्षेत्र के कुछ गांवों में शराब के सेवन से लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित गांवों में पहुंचकर घटना से संबंधित लोगों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान अवैध शराब के निर्माण एवं सप्लाई से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये। जांच में सामने आया कि बण्डा क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा मिलकर सागर गोल्ड के नाम से नकली शराब तैयार कर आसपास के गांवों में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने कार्यवाही करते हुये एक आरोपी के मक्का के खेत तथा अन्य स्थानों से शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की। पुलिस ने मौके से 164 सागर गोल्ड कंपनी एवं प्लेन मदिरा के खाली क्वार्टर, करीब 27 लीटर अमानक शराब, लगभग 170 क्वार्टर के ढक्कन, करीब 150 लेबल, शराब मापने का यंत्र, फेवीकॉल, टेप, ब्लेड, शराब भरने के लिये छोटी-बड़ी दो चुग्गियां तथा 11 कार्टून के गत्ते सहित अन्य सामग्री जब्त की है। थाना बण्डा के अपराध क्र. 658/26 में कुल 62.4 लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें आरोपी जुझार सिंह लोधी निवासी बौराज से 43.2 लीटर शराब बरामद की गई। वही थाना विनायका के अपराध क्र. 98/26 में कुल 189.72 लीटर शराब जब्त की गई। इसमें मुख्य आरोपी चन्द्रभान उर्फ चंदू सिंह राजपूत निवासी ततरवारा से 147.6 लीटर शराब बरामद होना बताया गया है। इस प्रकार दोनों मामलों में पुलिस द्वारा कुल 252.12 लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि जन्माष्टमी से दो दिन पूर्व ततरवारा क्षेत्र में मक्का के खेत में शराब तैयार करने की गतिविधि की गई थी। पुलिस के अनुसार तैयार की गई नकली शराब को नौराज, गूगरा, पाटन, छापरी एवं आसपास के गांवों में सेल्समैन के माध्यम से सप्लाई किया गया था। पुलिस कार्यवाही की भनक लगने पर आरोपियों द्वारा अवैध शराब एवं निर्माण सामग्री को नष्ट करने का प्रयास किये जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई है। थाना बण्डा पुलिस ने मनोहर लोधी, दिनेश लोधी, जुझार लोधी, राजा लोधी, अनिकेत गंधर्व, रविन्द्र, आकाश राय और गोविन्द्र लोधी को गिरफ्तार किया है। थाना विनायका में अरविन्द्र यादव, भगवान सिंह लोधी, मानसिंह अहिरवार, चन्द्रभान उर्फ चंदू राजपूत, धर्मेन्द्र राजपूत, सोहन राजपूत, रोहित शिवहरे और राघवेन्द्र राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। मामले में संदीप लोधी उर्फ यशवंत सिंह ठाकुर निवासी बण्डा, रवि लखेरा निवासी महेवा तथा शिवान्जय निवासी छापरी फरार बताये गये हैं। पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। पुलिस ने मनीष लोधी उर्फ यशवंत लोधी निवासी बण्डा एवं रवि लखेरा की गिरफ्तारी पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। वही शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये 10-10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। पुलिस जांच में कुछ आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आये हैं। पुलिस के अनुसार रवि लखेरा के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर करीब 25 अपराध पंजीबद्ध हैं, जबकि चन्द्रभान उर्फ चंदू राजपूत के विरुद्ध पांच अपराध दर्ज होना बताया गया है। वही संबंधित अन्य आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अवैध शराब के पूरे नेटवर्क, इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों तथा शराब की सप्लाई के स्रोत के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

स्वामी पत्रकार प्रकाशन प्रा.लि.के लिए प्रकाशक गिरिराज चाचा मुद्रक गिरिराज चाचा द्वारा दैनिक भास्कर प्रेस (डी बी कार्प लि.) प्लाट नं. 36 इंडस्ट्रीयल एरिया सागर म.प्र. सागर से मुद्रित एवं 56 अग्रवाल बिल्डिंग एक्सिस बैंक के पीछे 10 सिविल लाईन्स, सागर मप्र से प्रकाशित, संपादक: **पलाश सुरजन,** कार्यकारी संपादक: **ज़ाकिर अली***
प्रबंध संपादक **डॉ. योगेश दत्त तिवारी** फोन 07582-228742 ई-मेल. deshbandhusgr@yahoo.in **प्रेस पंजीयन**- MPHIN/2016/69061 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।